

[2023] 5 एस. सी. आर 20

प्रशांत कुमार साहो और ओआरएस।

बी.

चारुलता साहू और ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील सं. 2913-2915)

29 मार्च, 2023

[ए. एस. बोपन्ना और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-शासन करने वाले कानून में संशोधन

पक्षकार-- विभाजन विभाजन मुकदमा - धारा 6,1956 अधिनियम को अंतिम डिक्री कार्यवाही के समापन से पहले 2005 के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था।

का प्रभाव-आयोजित: विभाजन मुकदमे पर चरणों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और इसे पूरी तरह से और पूरी तरह से अंतिम डिक्री पारित होने पर ही तय किया जा सकता है-इस प्रकार, पार्टियों को नियंत्रित करने वाले कानून को अंतिम डिक्री के समापन से पहले संशोधित किया गया था। कार्यवाही, पार्टी इस तरह के संशोधन से लाभान्वित (दोनों की तरह)

वर्तमान मामले में बेटियाँ) निचली अदालत से संशोधन का संज्ञान लेने और उसे लागू करने का अनुरोध कर सकती हैं-वादी जो वाद में निर्धारित अपने दिवंगत पिता की सभी संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से का हकदार है-मुकदमे द्वारा तैयार प्रारंभिक डिक्री। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए न्यायालय ने उक्त सीमा तक संशोधित किया-हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - एस. 6 2005 के संशोधन द्वारा यथा संशोधित-विनीता शर्मा मामले में व्याख्या-संशोधन से पहले और बाद में कानून की स्थिति-चर्चा-हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-O.XXIII, r. 3; Or.XLI, आर 22, o.XLIII, आर. 1-ए (2)-क्रॉस अपील-आयोजित की जा सकने योग्यता: अपील का अधिकार कानून का सृजन है-क्रॉस को प्राथमिकता देने का अधिकार।

आपत्ति एक अपील को प्राथमिकता देने के अधिकार का हिस्सा है-एक क्रॉस-अपील अपील के मूल अधिकार का प्रयोग है और केवल प्रक्रिया भिन्न होती है-क्रॉस-अपील ऑब्जेक्टर यू/का हकदार है। o.XLI, आर. 22 आर/डब्ल्यू O.XLIII, आर. 1-ए (2) इस निवेदन को सही बनाने के लिए कि वह निपटान समझौते की वैधता और वैधता पर सवाल उठाने के लिए कानूनी रूप से हकदार थी।

यू/O.XXIII दर्ज किया गया, आर. 3 प्रति-अपील के माध्यम से-इस प्रकार, वर्तमान मामले में, मूल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रति-अपील,

20 प्रशांत कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू

& ओआरएस।

समझौते की वैधता और वैधता पर सवाल उठाना कानून में बनाए रखने योग्य था।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XXIII, आर. 3-निपटान

सभी पक्षों की लिखित सहमति के बिना समझौता-की वैधता

-

आयोजित किया गया: Or.XXIII के अंतर्गत, आर. 3, जब वाद में किसी दावे को किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, तो समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उनके बीच एक पूर्ण समझौता होना चाहिए-वर्तमान मामले में, वादी ने समझौते के विलेख पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए, जिसे पहली अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था-इस प्रकार, यह गैरकानूनी था, सभी पक्षों की लिखित सहमति के बिना-संयुक्त संपत्ति के विभाजन के मुकदमे में, केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति से एक डिक्री को बनाए नहीं रखा जा सकता है-इसलिए, प्रतिवादी नं. 1 और 2 कानून के अनुसार नहीं था।

द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यास और प्रक्रिया समझौता याचिका

व्यक्त सहमति के बिना अधिवक्ता-न्यायालय के कर्तव्य-पर चर्चा की गई।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संदेह व्यक्त किया कि

प्रकाश में दिए गए कथन की शुद्धता क्योंकि प्रकाश और प्रकाश में दिए गए कथन के बीच एक स्पष्ट संघर्ष था।

दानम्मा। अधिनियम 1956 की धारा 6 की व्याख्या से संबंधित प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। वृहद पीठ ने अंततः विनीता शर्मा में कानून की स्थिति का निपटारा किया। बेटियाँ शिकायत में निर्धारित सभी संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से की हकदार हैं। वही अंतिम आदेश पारित करते समय विनीता शर्मा में दिए गए उक्ति के अनुसार होगा। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री के आधार पर, जिसकी उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी, उसमें तय किए गए मुद्दों को अंतिम माना जाएगा, लेकिन चूंकि विभाजन के मुकदमे का निर्णय चरणों में किया जाना आवश्यक है, इसलिए इसे पूरी तरह से और पूरी तरह से तब ही तय किया जा सकता है जब अंतिम डिक्री पारित की जाती है। चूंकि अंतिम डिक्री कार्यवाही के समापन से पहले पक्षों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन किया गया है,

ऐसे संशोधन से लाभान्वित पक्षकार (मामले में दो बेटियों की तरह) संशोधन का संज्ञान लेने और उसे प्रभावी बनाने के लिए विचारण न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में किसी भी त्रुटि को [2023] 5 एस. सी. आर. नहीं कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्षकारों के शेयरों का निर्धारण करते समय नीचे दिए गए न्यायालयों पर प्रतिबद्ध किया गया था। अब केवल 1956 के अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों में संशोधन को प्रभावी बनाने और तदनुसार पक्षों के शेयरों का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता है। वादी अपनी सभी संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से का हकदार है। स्वर्गीय पिता। यह मुद्दा कि क्या सभी संपत्तियां पैतृक थीं, जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से उठाया गया था, महत्वहीन हो जाता है।

[पारस 63,64,80 और 82] [56-ए-बी; 67-बी-डी, एफ]

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा और अन्य (2020) 9 एससीसी 1: [2020] 10 एस. सी. आर. 135-पर निर्भर।

प्रकाश और अन्य बनाम। फुलावती और अन्य (2016) 2 एस. सी. सी. 36 [2015] 12 एस. सी. आर. 579; दानम्मा उर्फ सुमन सुरपुर और एक अन्य बनाम। अमर और अन्य (2018) 3 एस. सी. सी. 343 [2018] 2 एस. सी. आर. 553-संदर्भित।

2.1 क्या उच्च न्यायालय मूल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रति-अपील को इस आधार पर स्वीकार करने में न्यायसंगत था कि अपीलकर्ताओं (प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2) के बीच समझौता सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 3 के तहत मान्य और बाध्यकारी नहीं था।

जब तक कानून अपीलार्थी को अधिकार और न्यायालय को ऐसा करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है, तब तक गुण-दोष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्रॉस-ऑब्जेक्शन को प्राथमिकता देने का अधिकार अपील को प्राथमिकता देने के अधिकार का हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 (प्रत्यर्थी) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील संख्या 2) कि सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 के तहत एक प्रति-अपील नियमित पहली अपील के रूप में प्रभावी है और यह तब भी कायम रहेगी, भले ही नियमित पहली अपील खारिज या वापस ले ली गई हो। एक प्रति-अपील अपील के मूल अधिकार का प्रयोग है और केवल प्रक्रिया भिन्न होती है। अपील का विरोध करने वाला सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 के तहत हकदार है जिसे आदेश एक्स. एल. आई. आई. के साथ पढ़ा जाता है।

सी. पी. सी. का नियम 1-ए (2), इस कथन को सही बनाने के लिए कि वह कानूनी रूप से सी. पी. सी. की वैधता और वैधता पर सवाल उठाने की हकदार थी।

सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 3 के तहत एक प्रति-अपील के माध्यम से दर्ज किया गया समझौता। प्रशांत कुमार साहो और ओ. आर. एस. द्वारा दायर क्रॉस-अपील।

बी. चारुलता साहू

& ओआरएस।

मूल प्रतिवादी संख्या 2, समझौते की वैधता और वैधता पर सवाल उठाना कानून में बनाए रखने योग्य था। [पारस 83,85,86,88,91] [67-जी-एच; 68-डी; 69-ई; 70-ए-बी; 74-एफ]

उर्मिला देवी और अन्य बनाम। शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (2020) 11 एस. सी. सी. 316 [2020] 3 एस. सी. आर. 498; बनवारी लाल बनाम। चंदो देवी (श्रीमती) और एक अन्य (1993) 1 एस. सी. सी. 581: [1992] 3 पूरका एस. सी. आर. 524; विपन अग्रवाल और एक अन्य बनाम। रमन गंडोत्रा और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1357 -

पर भरोसा किया।

वैध समझौता या समझौता, समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उनके बीच एक पूर्ण समझौता होना चाहिए। निर्विवाद रूप से, मामले में, वादी ने निपटान विलेख पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है, जिसे पहली अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। वादी ने खुद को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह कभी भी इसमें शामिल नहीं हुई उसके भाई यानी प्रतिवादी संख्या 1 और उसकी बहन यानी प्रतिवादी संख्या 2 के बीच समझौता। केवल इसी आधार पर, सभी पक्षों की किसी भी लिखित सहमति के बिना समझौते को गैरकानूनी कहा जा सकता है। संयुक्त संपत्ति के विभाजन के मुकदमे में, केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति से एक डिक्री नहीं रखी जा सकती है। [पारस 93,94] [76-ई-जी]

गुरप्रीत सिंह बनाम। चतुर भुज गोयल (1988) 1 एससीसी 270

: [1988] 2 एस. सी. आर. 401-पर निर्भर।

3. समझौता की वैधता और वैधता के संदर्भ में विचार के लिए तीसरा सवाल यह है कि क्या क्रॉस-ऑब्जेक्टर यानी प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता बिना किसी समझौते के समझौता याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते थे।

सहमति व्यक्त करें। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है

समझौता विलेख की वास्तविकता और वैधता। निर्विवाद रूप से, मामले में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न तो न्यायालय में पक्षों के बयान दर्ज किए थे और न ही समझौते की शर्तों की कोई जांच की थी। यह ऐसी परिस्थितियों में है कि उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि बेटियाँ वाद में निर्धारित सभी संपत्तियों यानी पैतृक और स्व-अर्जित संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से की हकदार हैं। स्वर्गीय श्री कुमार साहू। विचारण न्यायालय तदनुसार डिक्री में संशोधन करेगा। मूल प्रतिवादी Nos.1 और 2 के बीच समझौता कानून के अनुसार नहीं था, इसमें अपीलकर्ता मूल प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से के हकदार नहीं होंगे। अपीलार्थी मुकदमे की संपत्तियों में केवल अपने एक तिहाई हिस्से के हकदार होंगे। [पैरा 105] [85-एच; 86-ए-सी]

हिमालयन कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम। बलवान सिंह और अन्य (2015) 7 एस. सी. सी. 373: [2015] 4

एस. सी. आर. 616 पर भरोसा किया।

बाई चंचल और अन्य बनाम। सैयद जलालुद्दीन और अन्य (1970) 3 एस. सी. सी. 124: [1971] 2 एस. सी. आर. 171; बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम। भारतीय यूनियन बैंक और अन्य (1992) 1 एस. सी. सी. 31: [1991] 1 पूरक। एससीआर 187; डी. एस. लक्ष्मैया

और एक अन्य वी। एल. बालासुब्रमण्यम और एक अन्य

(2003) 10 एससीसी 310 [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 13; एल. आर. द्वारा जिनेश्वरदास (मृत)। और अन्य वी। जगरानी (श्रीमती) और एक अन्य (2003) 11 एस. सी. सी. 372 [2003] 4 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 17 9; एल. आर. के माध्यम से पुष्प देवी भगत (मृत)। साधना राय (श्रीमती) बनाम। राजेंद्र सिंह और अन्य (2006)

5 एस. सी. सी. 566 [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 370; गंडुरी

कोटेश्वरम्मा और एक अन्य वी। चकिरी यानादी और एक अन्य (2011) 9 एस. सी. सी. 788: [2011] 12 एससीआर 968; बद्रीनारायण शंकर भंडारी और अन्य बनाम।

ओमप्रकाश शंकर भंडारी आकाशवाणी 2014 बम 151

(एफ. वी.); यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बनाम

अभिजीत टी प्रसाद कुमार साहू और ओआरएस। वी. चारुलता सा

& ओआरएस।

कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2000) 7 एस. सी. सी. 357
: [2000] 3 पूरक। एस. सी. आर. 153-संदर्भित।

नित्यमोनी दासी बनाम। गोकुल चंद्र सेन (1911) 9 भारतीय

1924 कैल 80; गोविंदमल बनाम। मारिमुथु मिस्त्री और
अन्य ए. आई. आर 1959 मैड 7 का उल्लेख किया गया है। -

मामला कानून संदर्भ

[1971] 2 एससीआर 171

पैरा 28 (i)

संदर्भित किया गया है

[1991] 1 पूरक। एससीआर 187

पैरा 28 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 पूरक। एससीआर 13

पैरा 28 (iii)

संदर्भित किया गया है

[2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 17

पैरा 28 (iv)

संदर्भित किया गया है

[2006] 3 पूरक। एससीआर 370

पैरा 28 (vii)

संदर्भित किया गया है

[2011] 12 एससीआर 968

संदर्भित किया गया है

पैरा 30,38,59

[2015] 12 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा 61,63

[2018] 2 एससीआर 553

संदर्भित किया गया है

पैरा 61,62 और

6

[2000] 3 पूरक। एससीआर 153

संदर्भित किया गया है

पैरा 77

[2020] 10 एससीआर 135

उस पर भरोसा करें

पैरा 80

[2020] 3 एससीआर 498

उस पर भरोसा करें

पैरा 85

[1992] 3 पूरक। एससीआर 524

उस पर भरोसा करें

पैरा 89

[1988] 2 एससीआर 401

उस पर भरोसा करें

पैरा 93

[2015] 4 एससीआर 616

उस पर भरोसा करें

पैरा 101

2915 2018 से।

उच्च न्यायालय के 05.05.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2000 के ए. एच. ओ. सं. 133 और 2000 के एम. सी. सं. 24 में कटक में उड़ीसा

आर. बसंत, सीनियर एड. , अशोक पाणिग्रही, सुश्री गीतांजलि

कृष्णन, आर. चंदरदाचूड, सुश्री निकिता जयदेवन, नवाब सिंग वेंकटकृष्ण, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी. चित्तमबरेश, वरिष्ठ अधिवक्ता।, श्रीमती बी. सुनीता राव, गुनमाया मान, शिवाशीष मिश्रा, अनुराग, सोनल गुप्ता, सी. गोविंद वेणुगोपाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. चूँकि दोनों शीर्षक अपीलों में शामिल मुद्दे हैं

परस्पर संबंधित; पक्षकार भी समान हैं और चुनौती उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्वयं-समान निर्णय और डिक्री के लिए भी है, जिन्हें समान रूप से सुनवाई के लिए लिया गया था और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. दोनों शीर्षक अपीलें मूल प्रतिवादी संख्या 1 (स्वर्गीय श्री) के कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों के कहने पर की गई हैं।

प्रफुल्ल साहू एस/ओ कुमार साहू) और उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय, आदेश और डिक्री के खिलाफ निर्देशित हैं

कटक में उड़ीसा दिनांक 2000 के ए. एच. ओ. सं. 133 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर पत्र पेटेंट अपील को खारिज कर दिया, जिससे मूल वादी (प्रतिवादी सं. 1 इसमें) द्वारा स्थापित 1980 के शीर्षक वाद सं. 348 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और विभाजन की डिक्री की पुष्टि की गई और दूसरी ओर मूल प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दायर प्रति-आपत्तियों को अनुमति दी गई, जिससे स्वर्गीय प्रफुल्ल साहू और उनकी बहन के बीच किए गए पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज समझौते को रद्द कर दिया गया और घोषित किया गया कि वाद में प्रतिवादी सं. 2 अमान्य है।

फैक्ट मैट्रिक्स

3. यह मुकदमा कुमार साहू की पैतृक संपत्तियों के विभाजन से संबंधित है, जो अपीलकर्ताओं के बीच है जो कानूनी हैं।

नंबर 2 जो प्रतिवादी नंबर 2 (श्रीमती संतिलता डी/ओ कुमार साहू) के कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी हैं।

4. सुविधा के लिए, पक्षों के संबंध निम्नलिखित वंशावली तालिका से दिखाई देंगे, जो नीचे दी गई है:

- प्रशांत कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

हृदीबंधु

ध्रुवा

रोहि

ता

कुमार

अनंत

प्रफुल्

ल (मृत)

शांतिलता (मृत)

चारुलता

(प्र

तिवादी संख्या 1)

(प्रतिवादी संख्या 2)

(वादी)

| (

अपीलार्थी)

(प्रत्यर्थी संख्या 2)

(उत्तरदाता संख्या 1)

5. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से ऐसा प्रतीत होता है कि 1940 में किसी समय

विभाजन पर वादी के पिता स्वर्गीय श्री कुमार साहू, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को सह-पारसी के रूप में जवाब प्राप्त हुआ।

विषय गुण। 1969 में, जब श्री कुमार साहू का निधन हुआ, तो वे वादी और प्रतिवादी नं. 1 और 2 जवाब।

6. 3.12.1980 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 (यहाँ मूल वादी)

1980 का टी. एस. सं. 328 होने के नाते विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें शिकायत में निर्धारित 'ए' से 'एफ' की संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से का दावा किया गया।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 (यहाँ मूल वादी) ने प्रार्थना की

ऊपर निर्दिष्ट 1980 के स्वामित्व वाद सं. 348 में निम्नलिखित राहतें दी गई हैं:

“ (i) विभाजन के लिए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाए।

अनुसूची 'ए' से 'एफ' में वादी के एक तिहाई हिस्से का और

वादी को एक अलग स्थान पर उसी के विशिष्ट कब्जे में रखा जाए

द्वारा अंतिम डिक्री कार्यवाही में आवंटन को घुमावदार किया जा रहा है

सिविल न्यायालय सर्वेक्षण जानकार आयुक्त की नियुक्ति और प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध अपने लाभ के लिए एक डिक्री पारित की जाए।

1977 से मुकदमे की तारीख तक और मुकदमे की तारीख से

मुकदमे की संपत्तियों से उसी के भुगतान के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए।

((ii) प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाए।

अंतिम में वादी के अलग आवंटन में हस्तक्षेप करना

भविष्य में किसी भी समय कार्यवाही करने वाली डिक्री।

((iii) इसके विरुद्ध मुकदमे की लागत के लिए एक डिक्री पारित की जाए।

अभियुक्तों।

((iv) ऐसी अन्य राहत के लिए एक डिक्री पारित की जाए कि -

अंततः वादी को इसके खिलाफ अपने पक्ष में हकदार पाया जाता है

प्रतिवादी।

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सम्पत्तियों का विवरण

अनुसूची-ए

1. जिला-कटक, एस. आर. कटक, गाँव-चौलियागंज

सं. 233। पी. एस. मधुपत्र खाता सं. 34, प्लॉट सं. 1088 ए. सी. 0.465 डिस। खाता नं. 32, प्लॉट नं. 1088।

खाता नहीं। 33

प्लॉट नंबर 1086

ए. सी. 142. डिस।

खाता संख्या 260

प्लॉट नंबर 1087

ए. सी. 0.502 दे।

एसी 0.266 डेक

प्लॉट संख्या 818

प्लॉट नंबर 1090

एसी 0.012 डेक

खाता संख्या 264

एसी 1.508 डेक

(ए. वी. रु. 1,03,930 / -)

अनुसूची-'बी'

मौज़ा-पैसा (हाल-गंदरपुर)

ए. सी. 0.48 डिस।

खाता नं. 108

प्लॉट नं. 110

खाता संख्या 106

ए. सी. 0.89 डिस

प्लॉट नंबर 98,

प्लॉट नंबर 97

खाता नं.-डो

ए. सी. 0.09 डिस।

प्लॉट नंबर 99

ए. सी. 0.14 डिस

प्लॉट नंबर 100

ए. सी. 0.37 डिस।

खाता नं. 107

ए. सी. 0. 17 डिस

प्लॉट नंबर 95

ए. सी. 0.45 डिस।

खाता नं. 184

प्लॉट नंबर 101

प्लॉट संख्या 199 एसी। 0.21- 1/4 1/2 डिस।

खाता नं. 114

ए. सी. 0.10 डिस।

खाता नं. 8

प्लॉट नंबर 96

ए. सी. 2.90 - 1/2 डी

(. ए. वी. आर. एस. 2850 / -)

अनुसूची-'सी'

जिला-कटक। एस. आर. कटक, मौज़ा-राजहंस, ओ एंड ओआरएस।

बी. चारुलता साहू 2 3. पारदीवाला, जे।]

ए. सी. 0.18 डिस

प्लॉट नं. 316।

ए.

प्लॉट नंबर 535

ए. सी. 0.08 डिस।

प्लॉट संख्या 539

ए. सी. 0.02 डिस

प्लॉट संख्या 548

ए. सी. 0.03 डिस।

बी.

ए. सी. 0.41 डिस।

प्लॉट संख्या 553

ए. सी. 0.72 डिस।

एस.

अनुसूची-'डी'

दार, कटक,

..... ए. वी. रु.

अनुसूची-'ई'

डी.

चाटा नं. 1 प्लॉट नं. 73 एसी। 0.13 डिस।

ए. सी. 0.12 डिस

ए. सी. 0.25 डिस

ई.

ए. सी. 0.12 डिस।

प्लॉट नंबर 85

ए. सी. 0.14 डिस

प्लॉट नंबर 87

ए. सी. 0.18 डिस।

प्लॉट नंबर 93

ए. सी. 0.19 डिस।

प्लॉट नं. 70

एफ.

ए. सी. 0.29 डिस।

प्लॉट नं. 72

ए. सी. 0. 19 डिस।

प्लॉट नं. 104

ए. सी. 1.10 डिस

जी.

. जिसका मूल्य रु। 205 /

प्लॉट नंबर 128

ए. सी. 0.50

ए. सी. 27.59 डिस

प्लॉट नंबर 135

प्लॉट नं. 17

ए. सी. 1.93 डिस

एच बी

[2023]

ए.

ए.

सी. 2.22

प्लॉट नंबर 180

ए.

सी. 10.18

प्लॉट नं. 181

प्लॉट नंबर 127

ए.

सी. 2.13

प्लॉट नंबर 130

ए.

सी. 1.23

प्लॉट नं. 101/186

ए. सी.

प्लॉट नंबर 132

ए.

सी.

0.35

ए. सी. 0.35

प्लॉट नंबर 132

प्लॉट नंबर 137

ए. सी.

सी.

प्लॉट नंबर 136

ए.

सी. 0.26

प्लॉट नं. 99/185 AC। 0.42

नं. 47.25 डिस। जिसका मूल्य रु। 450 /

प्लॉट नंबर 75

ए.

सी. 0.31

खाता नं. 19

डी.

प्लॉट नंबर 64

ए.

सी.

0.22

ए. सी. 0.30

प्लॉट नं. 74

ए.

सी. 0.15

प्लॉट नं. 79

प्लॉट नंबर 34

ए.

सी. 0.15

ई.

प्लॉट नंबर 38

ए.

सी. 0.11

प्लॉट नंबर 69

सी.
ए. सी. 0.37

ए.
0.23

प्लॉट नंबर 68

एफ.
सी. 1.74

कन

ए.
मूल्यां

खाता नं. 21

प्लॉट नंबर 145

सी.
ए. सी. 0.30 ए

ए.
0.68

प्लॉट नं. 71

जी.

प्लॉट नंबर 58

सी.
ए. सी. 0.03

ए.
0.22

प्लॉट संख्या 182

प्लॉट नं. 57

सी. 0.21

ए.

प्लॉट संख्या 194

सी. 0.20

ए.

एच ओ एंड ओआरएस। वी. चारुलता साहू 3 3. पारदीवाला, जे।]

ए. सी. 0.11 डिस।

प्लॉट नंबर 107

ए.

ए. सी. 0.25 डिस।

प्लॉट नंबर 139

ए. सी. 0.06 डिस।

प्लॉट नंबर 83

बी.

ए. सी. 3.06 डिस

मूल्यांकन रु। 595 /

अनुसूची-'एफ'

% . सदर, एस. आर. कटक, जिला-कटक।

एस.

ए. सी. 0.080 डिस।

प्लॉट नंबर 51

ए. सी. 0.023 डिस।

प्लॉट नंबर 54

ए. सी. 0.012 डिस।

प्लॉट नं. 57

डी.

प्लॉट नं. 61

ए. सी. 0.035 डिस।

ए. सी. 0.22 डिस।

प्लॉट नंबर 62

ए. सी. 0.006 डिस।

प्लॉट नंबर 91

प्लॉट नंबर 93

ए. सी. 0.007 डिस।

ई.

ए. सी. 0.044 डिस।

प्लॉट नं. 108

ए. सी. 1.89 दशमलव

..... रुपये/1.890 /

एफ.

लैंड्स एसी। 60.79 डिस।

..... रुपये में मूल्य। 1.20 , 610 /

वेरिफिकेशन "।

निम्नलिखित मुद्दे:

जी.

कानून में सक्षम?

प्रतिवादी संख्या 2 शहरी भूमि की शुरुआत के बारे में परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण टी, 1976, और क्या वादी बनाए रख सकता है

एच.

ई सूट संपत्ति?

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) क्या मुकदमे की संपत्ति पक्षकारों के बीच विभाजन के लिए उत्तरदायी है?

(4) वादी, प्रतिवादी के संबंधित शेयर क्या हैं?

मुकदमे की संपत्ति में नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2?

(5) सूट में कौन सी संपत्ति कुमार साहू की पैतृक और स्व-अधिग्रहित है?

(6) मेसन लाभ में वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के क्या शेयर हैं और वे किस तारीख से इसके हकदार हैं?

(7) क्या विभिन्न पक्षों द्वारा अलग-अलग समय पर मुकदमे की संपत्ति से किए गए अलगाव को उनके साथ समायोजित किया जाना है

संबंधित शेयर? (8) क्या स्वर्गीय निसमानी देई द्वारा निष्पादित निपटान विलेख दिनांक 20.07.1985 पर कार्रवाई की गई है और वे वादी हैं।

और प्रतिवादी संख्या 2 उसी से बंधे हैं?

(9) क्या प्रतिवादी संख्या 1 के हाथ में संपत्ति के कथित निर्माण के लिए पर्याप्त संयुक्त परिवार केंद्र था?

संयुक्त परिवार?

(10) क्या अनुसूची ई में खाता संख्या 18 की संपत्ति

संशोधित शिकायत विभाजन के लिए उपलब्ध है?

(11) पक्ष किस राहत के हकदार हैं?

निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया और कहा कि वादी का पैतृक संपत्ति में छठा हिस्सा और एक तिहाई हिस्सा था। अलग संपत्ति में हिस्सेदारी। उक्त फरमान जारी किया जा रहा है

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती दी गई। ”

9. पक्षों के बीच मुकदमे का निर्णय लिया गया और सिविल न्यायाधीश ने दिनांक 30.12.1986 के आदेश के माध्यम से एक प्रारंभिक ई निम्नानुसार तैयार किया:

आदेश

मुकदमे का फैसला प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा पर प्रारंभिक रूप से किया जाता है।

नहि: 1 लागत के साथ डी-2 बिना लागत के। वादी पैतृक और स्व-अर्जित संपत्तियों और सुपर स्ट्रक्चर के संबंध में 2 आना 8 पाई (1/6) शेयर और 1/3 हिस्से का हकदार है। उस पर (घर और इमारतें)

क्रमशः स्वर्गीय कुमार चरण साहू की सूट संपत्तियों से बाहर।

वह आसंता कुमार साहू और ओआरएस की भी हकदार हैं। बी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मुक्रदमे की स्थापना की तारीख। प्रतिवादी संख्या-2 भी हकदार है।
समान हिस्से के लिए। प्रतिवादी सं:

संपत्तियों और मुनाफे के

1 में 10 आना 8 पाई (2/3) और 1/3 शेयर का हकदार है।

क्रमशः पैतृक और स्व-अर्जित संपत्तियाँ और

उस पर स्वर्गीय कुमार चरण साहू और मेन्से की अधिरचना

उससे होने वाला लाभ। एक अमीन आयुक्त को प्रतिनियुक्त किया जाना है

उपरोक्त आधार पर विभाजन करने वाला अंतिम डिक्री कौन है

कार्यवाही उपरोक्त आधार पर शेयरों का विभाजन करेगी

पैतृक और स्व-अर्जित विवरणों का पता लगाना

गुण उस पर एक अधिरचना और क्वॉंटम भी

प्राप्त संकेतों और निष्कर्षों के आलोक में मुनाफे का

ऐसे भाग वादी और प्रतिवादी सं. का निर्धारण: 2

ऐसी संपत्तियों के कब्जे में रखा जाना है जो

अंतिम डिक्री के परिणामस्वरूप उन्हें अलग से आवंटित किया गया

आगे बढ़ रहे हैं। विवादित उपयोग योग्य पर सुनवाई शुल्क '।

10. इस प्रकार, निचली अदालत ने निर्देश दिया कि:

(i)

अनुसूची 'ए' से 'एफ' में सूचीबद्ध गुण जिनका उल्लेख किया गया है

उपरोक्त को पैतृक संपत्ति माना जाएगा, जबकि अनुसूची 'जे' (1 से 8 संपत्तियाँ) में सूचीबद्ध संपत्तियों को स्वर्गीय श्री की स्व-अर्जित संपत्तियों के रूप में माना जाता था।

कुमार साहू।

((ख)

प्रत्यर्थी संख्या 1 (यहाँ मूल वादी) आयोजित किया गया था

पैतृक संपत्तियों में एक तिहाई और एक तिहाई हिस्से का हकदार स्वर्गीय श्री कुमार साहू की स्व-अर्जित संपत्तियों में हिस्सेदारी। दीवानी अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वादी बहुत अधिक लाभ का हकदार था।

((ग) प्रतिवादी सं. 2 को अर्जित समान अंश और लाभ।

(उत्तरदाता सं. 2)

((iv) प्रतिवादी संख्या 1 (यहाँ वादी) को स्वर्गीय श्री कुमार साहू की पैतृक संपत्तियों में 4/6 वें हिस्से और स्व-अर्जित संपत्तियों में 1/3 वें हिस्से का हकदार ठहराया गया था।

मेसन लाभ सहित।

11. यह ध्यान रखना उचित है कि ऊपर निर्दिष्ट निर्णय और डिक्री ट्रायल कोर्ट के खिलाफ, यह केवल प्रतिवादी संख्या 1 है, जो उड़ीसा के उच्च न्यायालय के समक्ष 1986 की एफ. ए. संख्या 359 दायर करने के लिए उपयुक्त है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह अपील अनिवार्य रूप से इस आधार पर दायर की गई थी कि स्वर्गीय श्री कुमार साहू की सभी संपत्तियों को पैतृक संपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए था।

12. अभिलेख पर सामग्री से यह प्रतीत होता है कि जबकि पहली

ऊपर निर्दिष्ट अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी,

प्रतिवादी सं. 2 (प्रतिवादी सं. 2) ने प्रतिवादी सं. 1 के साथ एक समझौता किया, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुसार रुपये पर विचार करने के बदले में अपना हिस्सा छोड़ दिया। 50 , 000 / - और अनुसूची 'ए' और 'बी' में भूमि के हिस्से। ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र पर विधिवत हस्ताक्षरित 29.03.1991 दिनांकित एक समझौता याचिका। 1 और 2 उत्तर, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था जो ऊपर निर्दिष्ट 1986 के एफ. ए. संख्या 359 में 1990 के विविध मामले संख्या 643 के रूप में दर्ज किया गया था।

13. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1986 के एफ. ए. सं. 359 का निपटारा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 4. इस अपील में, पहले यह तर्क दिया गया है कि पिता द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान बेटियों को कुछ संपत्तियां दी गई थीं और कुछ संपत्तियां उनकी शादी के समय उन्हें उपहार में दी गई थीं और कुछ अन्य संपत्तियां पिता द्वारा दोनों के नाम पर खरीदी गई थीं।

बेटियाँ, अर्थात् वादी और प्रतिवादी संख्या 2, पिता की मृत्यु के बाद किसी भी अलग हिस्से की हकदार नहीं हैं।

5. उपहार की वैधता के लिए कोई चुनौती नहीं है।

विवाह के समय बेटियों के पक्ष में कार्य, यदि कोई हो। यह इंगित करने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है कि कुछ संपत्तियों को नाम-उधारदाताओं के रूप में बेटियों के नाम पर खरीदा गया था और वास्तव में संपत्ति की थी

पिता। इसलिए, यह मानते हुए भी कि कुछ संपत्तियों को उपहार में दिया गया था और वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर खरीदा गया था, जो इसे नकारने का आधार नहीं हो सकता है।

वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तराधिकार का अधिकार, जो

पिता की मृत्यु के बाद अर्जित।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि कुछ संपत्तियाँ स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 की स्व-अर्जित संपत्तियाँ थीं। लिखित कथन के अवलोकन से संकेत मिलता है कि लिखित कथन में ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं बनाया गया था, और न ही ऐसी कोई सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है।

आसंता कुमार साहो और ओआरएस में। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नाम के लायक किसी भी साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए इस तरह के तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है।

7. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि अपील के लंबित रहने के दौरान, वर्तमान अपीलार्थी और उसके बीच एक समझौता किया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या 2, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ दिया है। इस तरह से

समझौता अन्यथा वैध है और यह वादी के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है, इसे प्रभावी बनाया जा सकता है और निचली अदालत की डिक्री को तदनुसार संशोधित किया जाना है।

8. इस प्रकार, हालांकि अपीलार्थी की अन्य सभी दलीलें स्वीकार्य नहीं हैं, समझौते को देखते हुए निचली अदालत की डिक्री को इस हद तक संशोधित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 भी प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, वह पैतृक संपत्ति में 5/6 वें हिस्से और अलग-अलग संपत्तियों में 2/3 वें हिस्से का हकदार होगा जैसा कि निचली अदालत द्वारा निर्धारित किया गया है। निचली अदालत की डिक्री को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि अपील के लंबित रहने के दौरान, प्राप्तकर्ताओं को अलग-अलग समय पर नियुक्त किया गया था और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1-अपीलार्थी प्राप्तकर्ता के रूप में जारी है। यह आगे प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में कुछ राशियाँ जमा की गई हैं जिन्हें सावधि जमा में रखा गया है। इस न्यायालय में सावधि जमा का उचित अवधि के लिए समय-समय पर नवीनीकरण किया जाएगा।

अधिकतम ब्याज प्राप्त करें। जो राशि अभी तक सावधि जमा में नहीं रखी गई है, उसे भी इसी तरह सावधि जमा में रखा जाएगा ताकि राशि का वितरण अंतिम आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार किया जा सके।

अंतिम डिक्री की कार्यवाही समाप्त हो गई है। यदि पक्षकार किसी सौहार्दपूर्ण व्यवस्था पर नहीं आते हैं, तो वादी या प्रतिवादी संख्या 1 अंतिम डिक्री की कार्यवाही शुरू कर सकता है। निचली अदालत किसी भी उचित व्यय आदि के प्रति आवश्यक समायोजन करने के बाद, इस निर्णय में अब बताए गए शेषों के अनुसार राशि के वितरण के संबंध में एक निर्देश पारित करेगी। रिसीवर अब से ट्रायल कोर्ट के निर्देश के तहत कार्य करेगा और संपत्तियों के लेखांकन और रखरखाव आदि से संबंधित सभी आवश्यक दायित्व ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और यदि [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोई भी जमा प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक है, वही

विचारण न्यायालय में किया जाएगा जो ऐसा ही करेगा

सावधि जमाओं के संबंध में व्यवस्था। के लिए आवेदन

प्राप्तकर्ता को हटाने या कोई नई शर्तें लागू करने के लिए

निचली अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता है जो इससे निपटने के लिए स्वतंत्र है

(जोर दिया

गया)

ऐसे सभी अनुप्रयोग।

14. प्रतिवादी संख्या 1 (यहाँ अपीलकर्ता) ने जारी रखा

उड़ीसा उच्च न्यायालय, 1948 के नियमों के अध्याय VI के तहत लेटर्स पेटेंट अपील दायर करके मुकदमा। लेटर्स पेटेंट अपील अनिवार्य रूप से इस आधार पर दायर की गई थी कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश इस मुद्दे पर सही निर्णय लेने में विफल रहे थे कि क्या शिकायत की अनुसूची में उल्लिखित कुछ संपत्तियां स्वर्गीय श्री कुमार साहू की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं या सभी संपत्तियां पैतृक संपत्तियां थीं।

15. प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी) के समक्ष अपील की गई

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि सभी संपत्तियां पैतृक थीं क्योंकि वे मौजूदा पैतृक संपत्तियों के एक ही केंद्र से प्राप्त होती हैं। डिवीजन बेंच के समक्ष अपील को अपील नं. 2000 का ए. एच. ओ. सं. 133।

16. 28.06.2001 पर, प्रतिवादी संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ)

2000 के ए. एच. ओ. सं. 133 में प्रति अपील के माध्यम से ऊपर निर्दिष्ट निपटान विलेख की वैधता को चुनौती दी गई।

17. अपीलार्थियों द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील में,

न्यायालय ने निर्धारण के निम्नलिखित बिंदुओं पर खुद को संबोधित किया:

" (i) क्या इस पर दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारण

विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा विवादास्पद मुद्दे या तो हैं इसके द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले कानून में त्रुटि या त्रुटि

अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय?

((ii) क्या प्रथम अपीलीय न्यायाधीश ने

पहले प्रतिवादी द्वारा उपयुक्त आधार तैयार करके आग्रह किए गए आधार
विवादास्पद मुद्दों पर दर्ज किए गए निष्कर्षों को इंगित करें
विद्वत् विचारण न्यायालय, इस न्यायालय के साथ हस्तक्षेप की आवश्यकता है
हालाँकि इस अपील में विवादित निर्णय, इस न्यायालय का
इस लेटर पेटेंट अपील में अधिकार क्षेत्र भी समान है
पहला अपीलीय न्यायालय?

प्रशांत कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

((iii) क्या निष्कर्ष अंक सं. में दर्ज किए गए हैं। 5 , यह मानते हुए कि कुछ अनुसूची संपत्तियाँ स्व-अर्जित संपत्तियाँ हैं

स्वर्गीय कुमार साहू की याचिका कानूनी रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण है और इस अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है?

((iv) क्या वकील द्वारा दायर समझौता याचिका

विशेष अपील के बिना पहली अपील में प्रतिवादी 1 और 2 समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उनके पक्ष में प्राधिकरण

प्रतिवादी द्वारा याचिका सं। 2 , और वादी समझौता याचिका का पक्षकार नहीं है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जा सकता था और जहां तक प्रतिवादी को सौंपा गया हिस्सा है, वहां तक निचली अदालत के फैसले को संशोधित किया जा सकता था। 2 , वैसा ही

क्या यह वैध और वैध है?

((v) पक्षकार किस आदेश के हकदार हैं?

18. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने आक्षेप के माध्यम से

5.05.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश ने प्रतिवादी संख्या 1 (यहाँ अपीलकर्ता) द्वारा दायर 2000 की ए. एच. ओ. संख्या 133 की अपील को खारिज कर दिया और

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रति अपील की अनुमति दी गई। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादियों के बीच किए गए समझौते को शून्य कर दिया।

19. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी (कानूनी)

मूल प्रतिवादी संख्या 1) के उत्तराधिकारी वर्तमान अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष हैं।

अपीलार्थियों के स्वयं के बारे में सुझाव

20. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों ने एक गंभीर अपराध किया है।

यह निष्कर्ष दर्ज करने में त्रुटि कि अनुसूची 'जे' (1 से 8 संपत्तियाँ) में संपत्तियाँ स्वर्गीय श्री कुमार साहू की स्व-अर्जित संपत्तियाँ थीं।

श्री बसंत के अनुसार वादी और प्रतिवादियों को हस्तांतरित की जाने वाली सभी संपत्तियाँ पैतृक प्रकृति की हैं। 21. यह प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि स्वर्गीय श्री कुमार साहू के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत था

जिसके माध्यम से, उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान कुछ संपत्तियों का अधिग्रहण किया था जो पैतृक संपत्तियों का हिस्सा नहीं हैं। श्री बसंत के अनुसार, जे श्रृंखला की संपत्तियाँ (1 से 8 संपत्तियाँ) स्वर्गीय श्री

कुमार साहू द्वारा पैतृक संपत्तियों से प्राप्त आय की सहायता से खरीदी गई थीं और ऐसी परिस्थितियों में जे श्रृंखला (1 से 8 संपत्तियां)।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह मौजूदा पैतृक संपत्तियों के उसी केंद्र का हिस्सा होगा जिसे अब वादी और प्रतिवादियों को पैतृक संपत्तियों के रूप में हस्तांतरित किया गया था।

22. श्री बसंत ने इसके बाद हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रभाव पर न्यायालय को संबोधित किया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1956') में संशोधन अधिनियम, 2005 'या' 2005 संशोधन '। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी को इसके तहत अधिकारों को प्रभावित करने की याचिका उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए इतने वर्षों के बाद अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षण के लिए यह मानते हुए कि 2005 के संशोधन ने पक्षों के अधिकारों को बदल दिया है, विशेष रूप से, सह-पार्सनर के रूप में बहनों को, हालांकि, निपटान विलेख को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 (यहां मूल प्रतिवादी संख्या 2) के अधिकारों को कहा जा सकता है

बुझा दिए गए हैं और अपीलार्थियों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उसके पूरे हिस्से का हस्तांतरण मुकदमे की संपत्तियों में उसके हिस्से/अधिकारों का निपटान होगा। 1991 में हुई स्थिति को 2005 के संशोधन को देखते हुए अस्थिर होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

23. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2005 के संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव 1965 और 2005 के बीच किए गए अलगाव के लिए तबाही का कारण बनेगा और ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 1 (वादी) के अधिकार, यदि कोई हों, तो उत्तराधिकारियों को प्राप्त होंगे।

बोझ से भरी हुई पैतृक संपत्ति, जैसा कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के केंद्र के साथ उपलब्ध है, केवल 20.12.2004 से प्रभावी है।

24. श्री बसंत ने प्रस्तुत किया कि 20.12.2004 से पहले हुए अलगाव को फिर से नहीं खोला जा सकता है ताकि

यह पता लगाने के लिए कि विभाजन के लिए कौन सी संपत्तियां उपलब्ध हैं, मामला विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

आई. डी. 1 से पहले हुई संपत्ति को 2005 के संशोधन के कारण अमान्य या अलग रखा जाएगा।
26. श्री बसंत ने अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में विनीता शर्मा बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। राकेश शर्मा और अन्य ने (2020) 9 एस. सी. सी. 1 में, विशेष रूप से, पृष्ठ 58 पर पैरा 76 में टिप्पणियों की सूचना दी, जो इस प्रकार है:

प्रशांत कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" 76. यह तर्क दिया गया था कि यदि संसद का इरादा था कि

2005 से पहले जन्म की घटना प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी

एक सह-भागीदार का दर्जा, संसद को होने की आवश्यकता नहीं होगी

धारा 6 (1) के परंतुक को अधिनियमित किया। जब हम पढ़ते हैं

संयुक्त रूप से प्रावधान, जब अधिकार की बेटी को दिया जाता है

जन्म से एक बेटे के रूप में एक सह-भागीदार, यह बन गया
स्वभाव या अलगाव को बचाने के लिए आवश्यक, जिसमें शामिल हैं

कोई विभाजन या वसीयती उत्तराधिकार, जिसने

20-12-2004 से पहले रखें। एक बेटी अधिकार का दावा कर सकती है

और 9-9-2005 से, और परंतुक अमान्य होने से बचाता है

(जोर दिया

गया)

उपरोक्त लेन-देन "।

27. श्री बसंत ने प्रस्तुत किया कि इसका कोई उचित कारण नहीं था

उच्च न्यायालय प्रतिवादी संख्या के बीच निपटान विलेख की वैधता और निष्पादन पर गौर करेगा। 1 और 2
जवाब। यदि सभी गुण हैं

पैतृक माना जाता है, वादी कुल पैतृक संपत्ति के छोटे हिस्से का हकदार है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 कुल
पैतृक संपत्ति के छोटे हिस्से का पांचवां हिस्सा का हकदार होगा। उन्होंने कहा कि यदि यह निर्धारित किया
जाता है कि जे श्रृंखला की संपत्तियां (1 से 8 संपत्तियां) वास्तव में स्व-अर्जित हैं, तो वादी पैतृक संपत्ति के
छोटे हिस्से और स्व-अर्जित संपत्ति के एक तिहाई हिस्से का हकदार है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 कुल पैतृक
संपत्ति के छोटे हिस्से और स्व-अर्जित संपत्ति के दो तिहाई हिस्से का हकदार होगा।

28. उनके निवेदन के समर्थन में कि समझौता के बीच

प्रतिवादी सं। 1 और 2 जवाब विधिसम्मत, न्यायसंगत और उचित था, उन्होंने इस न्यायालय के
निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

(i) बाई चंचल और अन्य बनाम। सैयद जलालुद्दीन और अन्य

(1970) 3 एस. सी. सी. 124 में पैरा 8 में अभिलिखित,

((ii) बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और

(1992) 1 एस. सी. सी. 31 में पैरा 38-41 पर रिपोर्ट किए गए अन्य,

(iii) डी. एस. लक्ष्मैया और एक अन्य v. एल. बालासुब्रमण्यम

और पैरा 18 पर (2003) 10 एस. सी. सी. 310 में रिपोर्ट किया गया एक अन्य,

(iv) एल. आर. द्वारा जिनेश्वरदास (मृत)। और अन्य वी। जगरानी (श्रीमती)

और एक अन्य ने (2003) 11 एस. सी. सी. 372 में पैरा 7-8 पर रिपोर्ट किया और

(v) एल. आर. के माध्यम से पुष्प देवी भगत (मृत)। साधना राय (श्रीमती)

वी. राजेंद्र सिंह और अन्य ने (2006) 5 एस. सी. सी. 566 में पैरा 18,19,23-25 पर रिपोर्ट किया।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, श्री बसंत प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपीलों में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में संशोधन किया जाए।

तदनुसार।

स्वयं जवाबदेह के बारे में सुझाव

नहीं। 1 (मूल स्थान)

30. प्रत्यर्थी संख्या 1 (मूल वादी) की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री बी. सुनीता राव ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और डिक्री पारित करने में कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि विनीता शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए वादी अब स्वर्गीय श्री कुमार साहू की सभी संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से का हकदार है, जो मुकदमा दायर करने के समय उपलब्ध थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, गंडुरी कोटेश्वरम्मा और एक अन्य बनाम के मामले में। चकिरी यानादी और एक अन्य ने (2011) 9 एस. सी. सी. 788 में बताया कि प्रारंभिक डिक्री को बदली हुई परिस्थितियों की स्थिति में दिया/बदला या संशोधित किया जा सकता है, भले ही कोई अपील दायर नहीं की गई हो।

31. विद्वान वकील ने आगे कहा कि अधिनियम 1956 की धारा 6 में 2005 के संशोधन और विनीता शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए बेटियां सह-स्वामित्व वाली संपत्तियों में बेटे के बराबर हिस्से की हकदार हैं। द. स्वर्गीय कुमार साहू की बेटियों में से एक होने के नाते वादी पैतृक संपत्ति में बड़े और समान हिस्से का हकदार है और ऐसी परिस्थितियों में अब कानून के संचालन के कारण डिक्री को संशोधित करने की आवश्यकता है।

32. विद्वान वकील ने कहा कि वादी और प्रतिवादी अब पैतृक और स्व-अर्जित दोनों के एक तिहाई हिस्से के हकदार हैं।

स्वर्गीय कुमार साहू की संपत्तियाँ। अधिनियम 1956 की धारा 6 (1) के संशोधित प्रावधान के संचालन के सही महत्व को समझाते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 20.12.2004 से पहले अलगाव की अनुमति है, लेकिन अलगाव की गई संपत्ति सह-भागीदार के हिस्से में आएगी, जिसने अलगाव किया, अगर कोई कानूनी बाध्यकारी आवश्यकता साबित नहीं होती है। विद्वान वकील ने बताया कि विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अलगाव प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का एक हिस्सा होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मुकदमा दायर करने की तारीख के बाद कोई भी अलगाव लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित होगा। मुकदमा दायर करने से पहले अलगाव पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और उस संबंध में विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है।

प्रशांत कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

33. यह बताया गया कि अनुसूची में 4.408 एकड़ भूमि में से

' ए 'और' बी 'संपत्तियां, तत्काल विभाजन के लिए उपलब्ध बिना किसी राशि वाली संपत्ति 3.762 एकड़ (लगभग 94 गुंटा) है। यह भी बताया गया कि अनुसूची 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' जवाब में वाद संपत्तियों की पूरी सीमा विभाजन के लिए उपलब्ध है, जैसा कि प्रारंभिक डिक्री के समय था।

34. जहाँ तक प्रतिवादी संख्या के बीच समझौते का संबंध है। 1 और

2 , विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वादी कभी भी इसका हिस्सा नहीं था

समझौता। उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और न ही उन्होंने समझौता विलेख के किसी भी हिस्से पर हस्ताक्षर किए थे या समझौते की शर्तों पर सहमत हुए थे। विद्वान वकील के अनुसार, वादी कभी भी समझौते में शामिल नहीं हुआ। प्राप्ति राशि के संवितरण के मुद्दे पर

अदालत में जमा किए गए, वकील ने प्रस्तुत किया कि वादी 84 वर्ष की है और उसने 2013 की आई. ए. संख्या 44977,2019 की आई. ए. संख्या 127171 और 2022 की आई. ए. संख्या 190628 के रूप में कई आई. ए. दायर किए हैं।

रिसीवर। यह प्रस्तुत किया गया था कि वादी के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और उसे चिकित्सा के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है उपचार आदि।

35. उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए, 2022 के आई. ए. संख्या 190628 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए कथित चूक को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है:

" 1. सूट संपत्ति पर ऊपरी संरचनाओं का संशोधन

अदालत की अनुमति के बिना। (आई. ए. का प्रासंगिक पृष्ठ 10-13)

सूट संपत्तियों के संबंध में देय राशि:

2 .

ए। जल बिल -

रु. 51,478 /

बी। राजस्व कर -

रु. 80,733 /

- रु. 1,89,228.84

सी। बिजली के बिल

कुल

रु. 3,21, 439.84

(आई. ए. का प्रासंगिक पृष्ठ 14-15)

3 .

सूट संपत्तियों में दो जलसायों को अवैध रूप से भरना

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना (तहसीलदार, कटक नगर निगम की रिपोर्ट और प्राथमिकी)

तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले संलग्न हैं।

आई. ए. के प्रासंगिक पृष्ठ 17-20)

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूट पर 100 किलोवाट बिजली के ट्रांसफॉर्मर की स्थापना

4 .

अलग-अलग भूखंड के लिए अनुमति मिलने के बाद संपत्ति।

(आई. ए. का प्रासंगिक पृष्ठ 21)

5 .

500 केवीए के विद्युत उपकेंद्र के लिए अनुमति प्राप्त की गई

वादी के जाली हस्ताक्षर द्वारा वाद संपत्ति के लिए और

प्रतिवादी 2 (2016 में जबकि प्रतिवादी नं. 2 में मृत्यु हो गई

2008) (आई. ए. का प्रासंगिक पृष्ठ 22)

सूट संपत्तियों पर अधिकृत निर्माण के लिए एक मामला है

6 .

कटक विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया था

यू. सी. नं. 249/2016। (आई. ए. का प्रासंगिक पृष्ठ 23) "

36. विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 को तुरंत प्राप्तकर्ता के रूप में हटा दिया जाना चाहिए और वादी को संपत्तियों के प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए।

स्वयं जवाबदेह के बारे में सुझाव

एनओएस। 3 , 4 , 5 , 7 और 8 जवाब (कानूनी उत्तराधिकारी)

मूल रक्षा सं। 2)

37. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. चितम्बरेश ने चार मुद्दों पर खुद को संबोधित किया:

क्या शिकायत में निर्धारित संपत्तियाँ हैं

((i)

पूर्ववर्ती की पैतृक या स्व-अर्जित संपत्तियाँ

वादी और प्रतिवादी 1 और 2 के हित में और पक्ष किस हिस्से के हकदार हैं?

((ख)

क्या एक क्रॉस-अपील के उद्देश्य के लिए बनाए रखने योग्य है
कथित समझौते को चुनौती देना?

(iii)

क्या कथित निपटान विलेख दिनांकित 28.03.1991 है
आदेश XXIII नियम 3 सिविल संहिता के तहत वैध और बाध्यकारी
प्रक्रिया, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी')?

((iv) क्या समझौता प्रतिवादी द्वारा किया गया था।

नं. 1 और 2?

(v)

क्या वकील समझौता याचिका पर हस्ताक्षर कर सकता है
बिना किसी स्पष्ट सहमति के?

38. पहले मुद्दे पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि तीनों न्यायालयों यानी, निचली अदालत, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे की संपत्तियों की प्रकृति पर एक समवर्ती निष्कर्ष है।

वह प्रस्तुत करेगा कि प्रशांत कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वादी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2, बेटी और सह-खरीददार होने के नाते, अपने भाई यानी प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी) के साथ पैतृक संपत्तियों में समान हिस्से के हकदार हैं। वह प्रस्तुत करेंगे कि इस संबंध में कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है जैसा कि विनीता शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा समझाया गया है। इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, गंडुरी कोटेश्वरम्मा (ऊपर) के मामले में उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही वादी और प्रतिवादी द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई हो, लेकिन अंशों का निर्धारण विनीता शर्मा (ऊपर) में निर्धारित संशोधन और कानून के अनुसार करना होगा। विवाद में कथित समझौते में गिने गए हिस्से के अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 पैतृक संपत्ति में अतिरिक्त छठे हिस्से का हकदार होगा।

39. ऊपर निर्दिष्ट दूसरे मुद्दे पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एक क्रॉस-अपील इस उद्देश्य के लिए बनाए रखने योग्य है -

40. विद्वान वरिष्ठ वकील ने सी. पी. सी. के आदेश XLIII नियम 1-ए (2) के प्रावधानों की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। वह प्रस्तुत करेगा कि प्रति-आक्षेपकर्ता सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 के तहत, जिसे सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. आई. नियम 1-ए (2) के साथ पढ़ा जाता है, अपनी प्रति-अपील में यह तर्क देने का हकदार है कि कथित निपटान विलेख या समझौते को एक वैध समझौते के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था और सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 3 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

41. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रार्थना करते हैं कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण उन्हें खारिज किया जा सकता है और 2005 के संशोधन के अनुसार पक्षों के शेयरों का निर्धारण किया जा सकता है।

विश्लेषण

42. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए आते हैं:

(i) विनीता शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दिए गए कथन को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के अधिकारों को किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ii) क्या उच्च न्यायालय इसमें अपीलार्थियों (प्रतिवादी संख्या 1) और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच समझौता घोषित करने में उचित था।

(प्रतिवादी संख्या 1) अमान्य है? दूसरे शब्दों में, क्या उच्च न्यायालय मूल प्रतिवादी संख्या 2 (यहाँ प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दायर प्रति-अपील को अनुमति देने में सही था।

43. दोनों तरफ से प्रचार किए गए प्रतिद्वंद्वी निवेदन पर ध्यान देने से पहले, हमें हिंदू कानून के इतिहास और विकास के संबंध में एक उचित विचार देना चाहिए और साथ ही विधि आयोग की रिपोर्ट, संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट और 2005 के संशोधन द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन करने के संसद के सही इरादे का पता लगाने के उद्देश्य से संसद में पेश किए गए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को देखना चाहिए।

44. हमने बद्रीनारायण शंकर भंडारी और अन्य बनाम के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले से हिंदू कानून के इतिहास और विकास का पता लगाया है। ओमप्रकाश

शंकर भंडारी ने आकाशवाणी 2014 वम 151 (एफ. बी.) में रिपोर्ट किया।

पुराना हिंदू कानून

45. प्रधान अधिनियम के अधिनियमन से पहले, हिंदुओं को शास्त्रीय और प्रथागत कानून द्वारा कवर किया जाता था जो क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होता था।

क्षेत्र। मुख्य रूप से, भारत में हिंदू कानून के दो स्कूल थे।

दयाभागा जो भारत के पूर्वी भाग यानी बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था और मिताक्षर जो शेष भारत में प्रचलित था। मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के तहत, एक संयुक्त हिंदू परिवार में महिला को केवल भरण-पोषण/निर्वाह का अधिकार था, लेकिन संपत्ति पर विरासत का कोई अधिकार नहीं था। हिंदू संयुक्त परिवार का आधार एक सामान्य पुरुष पूर्वज था और परिवार की संपत्तियों को एक सह-सहभागी संपत्ति के रूप में रखा जाता था, जिसमें परिवार के पुरुष सदस्य को जन्म के आधार पर संपत्ति का अधिकार होता था और सह-सहभागी संपत्ति में उनका हित संयुक्त हिंदू परिवार में किसी पुरुष की मृत्यु या जन्म के आधार पर अलग-अलग रहता था। एक पुरुष सह-भागीदार की संपत्ति उस पर

मृत्यु मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू में उत्तरजीविता से गुजरती थी

कानून। कोई भी महिला सहसदस्यता की सदस्य नहीं है, हालांकि वह संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य है। सह-संस्थापक में आम तौर पर चार डिग्री होते हैं अर्थात् सामान्य पूर्वज (सह-संस्थापक), उनका बेटा, पोता और परपोते।

46. दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के तहत, बेटियों को भी अपने भाइयों के साथ समान हिस्सा मिला।

दयाभाग प्रसाद कुमार साहो और ओआरएस के तहत। बी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विद्यालय की संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित की जाती है न कि उत्तरजीवी द्वारा। इस स्कूल में, एक महिला सह-भागीदार हो सकती है। जहाँ तक दयाभाग स्कूल का संबंध था, वहाँ सह-आंशिक संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी। और हिंदू परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने अधिकार में संपत्ति रखेगा और संपत्ति का निपटान करने का हकदार होगा जैसा कि वह उपहार या वसीयत द्वारा उचित समझता है। उत्तरजीविता द्वारा संपत्ति को पारित करने की कोई अवधारणा नहीं थी और न ही दयाभाग स्कूल में एक हिंदू पुरुष ने केवल अपने जन्म के आधार पर संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया था। नतीजतन, महिलाओं को एक अधिकार था

दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में परिवार से संबंधित पुरुषों के अधिकारों के बराबर।

48. 1950 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (2) और (3) और 16 को तैयार करते समय, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की प्रथा को रोकने और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने की मांग की गई थी। संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हिस्सा। उपरोक्त संवैधानिक उद्देश्य के अनुरूप, संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अर्थात् प्रधान अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम बौद्धों, जैनों और सिखों सहित सभी हिंदुओं पर लागू होता है। यह एक वर्दी पहनता है और

विरासत की व्यापक प्रणाली और सभी हिंदुओं पर लागू होती है, चाहे

मिताक्षर या दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ द्वारा शासित। हालाँकि, मूल अधिनियम की धारा 6, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, ने उत्तरजीविता द्वारा संपत्ति के सह-विभाजन के नियम को काफी हद तक बरकरार रखा, हालाँकि इसने हिंदू पुरुषों को उनके सह-विभाजन भाग सहित उनकी संपत्तियों के संबंध में वसीयती स्वभाव का अधिकार दिया। पूर्ववर्ती धारा 6

प्रधान अधिनियम (पूर्व-संशोधित धारा 6) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सह-सहभागी संपत्ति में सह-भागीदार का हित, यदि मूल अधिनियम की धारा 30 के तहत वसीयत द्वारा निपटाया नहीं जाता है, तो पूर्व-संशोधित धारा 6 के संदर्भ में विभाजित होगा। पूर्व-संशोधित धारा 6 के मुख्य भाग में [2023] 5 एस. सी. आर. में अपनी मृत्यु के समय पुरुष हिंदू के अधिकार का प्रावधान किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सह-आंशिक संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। हालांकि, परंतुक में प्रावधान किया गया है कि यदि मृतक सह-भागीदार की कोई महिला रिश्तेदार है अधिनियम की अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट, तब संपत्ति पूर्व-संशोधित धारा 6 के संदर्भ में हस्तांतरित हो जाएगी। स्पष्टीकरण 1 में प्रावधान किया गया है कि उनकी मृत्यु से तुरंत पहले काल्पनिक विभाजन होगा ताकि मृतक सह-सहभागी को सह-सहभागी में हिस्सा आवंटित किया जा सके।

49. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हिंदू संहिता विधेयक मिताक्षर सह-अधिवेशन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। हालांकि, एक ही

इसका विरोध किया गया था और पूर्ववर्ती धारा 6 को प्रधान अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। नतीजतन, यदि सह-सहभागी संपत्ति में विभाजन हुआ, तो प्रत्येक पुरुष सह-सहभागी को अपना हिस्सा मिलेगा और मां और पत्नी/विधवा सह-सहभागी नहीं बनेंगे, बल्कि सह-सहभागी संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बेटी को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सह-स्वामित्व वाली संपत्ति। बेटी को केवल एक हिस्से के रूप में मिलेगा

सह-सहभागी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी, पूर्व के परंतुक को ध्यान में रखते हुए, काल्पनिक विभाजन पर सह-सहभागी संपत्ति में मृतक के हिस्से से

प्रधान अधिनियम की धारा 8 में संशोधन किया गया। प्रधान अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में, एक हिंदू पुरुष अपनी पूरी संपत्ति का निपटान कर सकता है, जिसमें वसीयत/वसीयत द्वारा सह-संपत्ति में उसका हित भी शामिल है और इस प्रक्रिया में अपनी महिला उत्तराधिकारियों को किसी भी हिस्से से वंचित कर सकता है।

संशोधन अधिनियम, 2005 का निर्माण

50. हिंदू कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपनी 174 वीं रिपोर्ट (मई 2000) में, भारत के विधि आयोग का विचार था कि

समानता सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक सुधारों का आह्वान किया गया। आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विभिन्न राज्यों में पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं

लैंगिक समानता लाने के लिए बनाया गया। लेकिन केरल को छोड़कर इन सभी राज्यों ने बेटीयों को सह-आंशिक अधिकार प्रदान करते हुए राज्य अधिनियमों के लागू होने से पहले शादी की गई बेटीयों को ऐसे अधिकारों से भी वंचित कर दिया।

51. विधि आयोग ने सिफारिश की कि बेटी को जन्म से सह-भागीदार बनाया जाना चाहिए और वह एक अधिकार प्राप्त करने की हकदार होनी चाहिए।

विभाजन और/या पुरुष सह-भागीदार की मृत्यु पर हिस्सेदारी। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि एक बेटी जिसकी शादी संशोधन अधिनियम के शुरू होने के बाद हुई है, वह पैतृक संपत्ति में हिस्से की हकदार होनी

चाहिए क्योंकि वह पहले ही सह-भागीदार बन चुकी है। उसकी शादी। विधि आयोग की एक और सिफारिश प्रधान अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 23 को समाप्त करना था जिसमें यह प्रावधान था कि एक महिला को प्रसाद कुमार साहू और ओआरएस के रूप में परिवार के घर में रहने का अधिकार होगा।

बी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य, लेकिन एक पुरुष के विपरीत, उसे परिवार के घर के विभाजन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आयोग ने सिफारिश की कि उसे परिवार के घर के संबंध में पुरुष के बराबर अधिकार होने चाहिए।

52. विधि आयोग ने यह भी कहा कि उत्तराधिकार का कानून संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि V के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त पांच राज्यों द्वारा बनाए गए कानून इस हद तक निरस्त हो जाएंगे कि वे संविधान के मूल अधिनियम के प्रतिकूल हैं।

संशोधन।

53. 20 दिसंबर, 2004 को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक 2004 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ववर्ती धारा 6 में संशोधन करने और मूल अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 23 को हटाने/हटाने की मांग की गई थी।

" संशोधन के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण

' प्रधान अधिनियम 'निम्नानुसार है:

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने निर्वसीयत उत्तराधिकार हिंदुओं से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध किया है और ऐसे अधिकार दिए हैं जो तब तक महिलाओं की संपत्ति के संबंध में अज्ञात थे। हालाँकि, यह उन लोगों के विशेष अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है जो हिंदू मिताक्षर सह-पार्टी के सदस्य हैं सिवाय इसके कि कुछ मामलों में मृत पुरुष के व्याज के हस्तांतरण के लिए नियम प्रदान करना। अधिनियम-विरासत की एक समान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ मिताक्षर और दयाभाग द्वारा शासित व्यक्तियों पर लागू होता है।

स्कूलों और उन लोगों के लिए भी जो पहले द्वारा शासित थे मुरुमकट्टयम, अलियासंतन और नम्बूदिर कानून "।

यह अधिनियम 72 एस. ए. के 28 द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो हिंदू है। 566.2011 धर्म अपने किसी भी रूप या विकास में

जिसमें एक वीरशैव, एक लिंगायत या ब्रह्म, परथन या आर्य समाज का अनुयायी; या किसी भी व्यक्ति के लिए जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है; या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। वसीयती स्वभाव के मामले में, यह अधिनियम लागू नहीं होता है और मृतक का हित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा नियंत्रित होता है।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. अधिनियम की धारा 6 ब्याज के हस्तांतरण से संबंधित है

सह-स्वामित्व वाली संपत्ति में पुरुष हिंदू और नियम को मान्यता देता है

सदस्यों के बीच उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण का प्रतिधारण सह सहभागी। मिताक्षरा कोपारसेनरी का

इसमें महिलाओं को शामिल किए बिना संपत्ति का अर्थ है कि

महिलाएं अपने पुरुष के रूप में पैतृक संपत्ति में विरासत में नहीं मिल सकती हैं।

समकक्षों को। बेटी को बाहर करके कानून

न केवल सह-स्वामित्व में भाग लेना

लिंग के आधार पर उसके भेदभाव में योगदान देता है

लेकिन उसके मूल के उत्पीड़न और निषेध का भी कारण बना है

संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार। होने के नाते

महिलाओं को सामाजिक न्याय प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य

समान अधिकार देने वाले कानून में आवश्यक बदलाव किए हैं। हिंदू मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में बेटियों को। द.

केरल विधानमंडल ने केरल संयुक्त हिंदू परिवार को लागू किया है।

प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975।

3. इसमें निहित भेदभाव को दूर करने का प्रस्ताव है

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में समान अधिकार देकर

हिंदू मिताक्षर सह-अधिवेशन में बेटियों के अधिकार

बेटों के पास जैसी संपत्ति है। अधिनियम की धारा 23 ए को अपात्र बनाती है

आवास के संबंध में विभाजन की मांग करने वाली महिला उत्तराधिकारी

जब तक पुरुष उत्तराधिकारी चुनते हैं तब तक एक संयुक्त परिवार द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता है उसमें अपने-अपने शेयरों को विभाजित करना। यह भी प्रस्तावित है कि

उक्त धारा को हटा दें ताकि महिला की अक्षमता को दूर किया जा सके

उस धारा में निहित उत्तराधिकारी। '

4. उपरोक्त प्रस्ताव निम्नलिखित सिफारिशों पर आधारित हैं -
174 वीं रिपोर्ट में निहित है।

भारत का विधि आयोग अपनी

महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के बारे में: के तहत प्रस्तावित सुधार
हिंदू कानून।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(जोर दिया गया)

54. विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित धारा के परंतुक में प्रदान किया गया है

कि संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने पर विवाहित बेटी पर लागू नहीं होगा और यह भी
कि

सुधार अधिनियम का विभाजन पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा यदि

संशोधन 'प्रसाद कुमार साहो एंड ओआरएस' के शुरू होने से पहले यह प्रभावित हुआ था।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एकट करें। इसके बाद उपरोक्त विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। स्थायी समिति ने एक महिला हिंदू के खिलाफ प्रचलित संपत्ति के अधिकार के संबंध में हिंदू कानून और लैंगिक असमानता के ऐतिहासिक विकास को दर्ज करने के बाद सुझाव दिया कि विधेयक की प्रस्तावित धारा 6 (1) के परंतुक 1 को अधिनियम के लाभ से हटा दिया जाना चाहिए।

55. स्थायी समिति ने यह भी सुझाव दिया कि हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन को संशोधन अधिनियम में ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि सभी उद्देश्यों के लिए विभाजन या तो पंजीकृत दस्तावेजों द्वारा या अदालत के डिक्री द्वारा होना चाहिए। हालांकि, जहां मौखिक विभाजन का अनुरोध किया जाता है, उसी का समर्थन समर्थन में साक्ष्य द्वारा किया जाना चाहिए। विधि आयोग द्वारा सुझाए गए अनुसार धारा 23 को हटाने से हिंदू महिलाएं परिवार के सदस्यों द्वारा कब्जा किए गए परिवार के घर के विभाजन की मांग कर सकेंगी, जैसे पुरुष सदस्य विभाजन की मांग कर सकते हैं।

56. इसके बाद, आई. डी. 1 पर, संशोधन अधिनियम, 2005 को 2005 के अधिनियम 39 के रूप में पारित किया गया। संशोधन अधिनियम, 2005 की धारा 3

प्रधान अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया। संशोधन अधिनियम, 2005 ने विवाहित बेटी को संशोधन का लाभ प्राप्त करने से बाहर कर दिया और 20.12.2004 (राज्यसभा में विधेयक को पेश करने की तारीख) से पहले किए गए विभाजन को छोड़कर मूल अधिनियम की धारा 6 (1) में एक परंतुक भी जोड़ा। मूल अधिनियम की धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि धारा 6 के प्रयोजनों के लिए अधिनियम विभाजन का अर्थ केवल पंजीकृत दस्तावेज या न्यायालय की डिक्री द्वारा विभाजन है।

57. दोनों तरफ से प्रचार किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को टालने से पहले, पूर्ववर्ती धारा 6 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा

मूल अधिनियम और मूल अधिनियम की संशोधित धारा 6 में, जैसा कि सुविधा के लिए संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रधान अधिनियम की पूर्व-संशोधित धारा 6 निम्नानुसार है:

" धारा 6: - सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण-जब इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय उसके पास मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज होता है, तो संपत्ति में उसका हित राज्य के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।

इस अधिनियम के अनुसार नहीं; [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि, यदि मृतक ने उसे अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार या पुरुष रिश्तेदार के साथ जीवित छोड़ दिया था

उस वर्ग में निर्दिष्ट जो ऐसी महिला के माध्यम से दावा करता है

सापेक्ष, मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में मृतक का हित बसीयतनामा द्वारा हस्तांतरित होगा या इस अधिनियम के तहत, जैसा भी मामला हो, निर्वसीयत उत्तराधिकार, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

स्पष्टीकरण 1-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से तुरंत पहले हुआ होता, भले ही वह दावा करने का हकदार था या नहीं।

विभाजन हो या न हो।

स्पष्टीकरण 2-इस धारा के परंतुक में निहित किसी भी बात का अर्थ उस व्यक्ति को सक्षम बनाने के रूप में नहीं लगाया जाएगा जिसने मृतक की मृत्यु से पहले खुद को सह-सदस्य से अलग कर लिया है।

या उसके किसी भी उत्तराधिकारी को निर्वसीयता पर उसमें निर्दिष्ट ब्याज में एक हिस्से का दावा करना।

58. संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 6, जो डब्ल्यू. ई. एफ. 9.09.2005 लागू है, इस प्रकार है। :

" 6. सह-आंशिक संपत्ति के ब्याज का हस्तांतरण।

(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर और उसके बाद से, मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में, एक सह-भागीदार की बेटी,

(क) जन्म से पुत्र की तरह ही अपने अधिकार में सह-भागीदार बनें;

(ख) सह-पक्षीय संपत्ति में उतने ही अधिकार हैं जितने उसे पुत्र होने पर होते;

(ग) उक्त सह-पक्षीय संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान देनदारियों के अधीन होगा, और हिंदू मिताक्षर सह-पक्षकार के किसी भी संदर्भ में सह-पक्षकार की बेटी का संदर्भ शामिल माना जाएगा: बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा

या किसी भी आसांत कुमार साहू और ओआरएस सहित किसी भी स्वभाव या अलगाव को अमान्य कर दें।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

संपत्ति का विभाजन या वसीयती निपटान जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुआ था।

(2) कोई भी संपत्ति जिस पर एक महिला हिंदू हकदार हो जाती है

उप-धारा (1) के आधार पर सह-स्वामित्व की घटनाओं के साथ उसके पास अधिकार होगा और इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उसे सक्षम संपत्ति के रूप में माना जाएगा -

उसके द्वारा वसीयतनामा स्वभाव द्वारा निपटाया जा रहा है।

(क) बेटी को वही हिस्सा आवंटित किया जाता है जो किसी को आवंटित किया जाता है। बेटा;

(ख) पूर्व-मृत बेटे या पूर्व-मृत बेटी का हिस्सा, जो उन्हें विभाजन के समय जीवित होता, ऐसे पूर्व-मृत बेटे या ऐसी पूर्व-मृत बेटी के जीवित बच्चे को आवंटित किया जाएगा; और (ग) किसी पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री के पूर्व-मृत बच्चे का हिस्सा, जैसा कि उस बच्चे को मिलता।

यदि वह विभाजन के समय जीवित था, तो पूर्व-मृत बेटे या पूर्व-मृत बेटी के ऐसे पूर्व-मृत बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

बनो। स्पष्टीकरण। — इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता यदि संपत्ति का विभाजन हुआ होता।

उनकी मृत्यु से तुरंत पहले, चाहे वे विभाजन का दावा करने के हकदार थे या नहीं। (4) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के बाद, कोई भी अदालत [2023] 5 एस. सी. आर. के किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने पिता, दादा या परदादा से केवल हिंदू कानून के तहत पवित्र दायित्व के आधार पर देय किसी भी ऋण की वसूली के लिए एक बेटे, पोते या परपोते के खिलाफ कार्यवाई, ऐसे बेटे, पोते या परपोते के लिए

ऐसे किसी भी ऋण का निर्वहन:

बशर्ते कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले अनुबंधित किसी भी ऋण के मामले में, इस उप-धारा में निहित कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।

(क) पुत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने का किसी भी लेनदार का अधिकार,

पोता या प्रपौत्र, जैसा भी मामला हो; या

(ख) ऐसे किसी ऋण के संबंध में या उसकी संतुष्टि में किया गया कोई अलगाव और ऐसा कोई अधिकार या अलगाव -

2004 . स्पष्टीकरण। इस धारा "विभाजन" के प्रयोजनों के लिए

इसका अर्थ है पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या किसी न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावित विभाजन।

59. इस उक्ति पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि इस अदालत ने नीता शर्मा (उपरोक्त) द्वारा निर्धारित किया है, हमें इस अदालत के फैसले पर गौर करना चाहिए।

गन्डूरी कोटेश्वरम्मा (ऊपर) का मामला। गांदूरी में

इस न्यायालय के जवाब में, पैरा 11,12,13 और 14 में,

वेद निम्नानुसार है:

" 11. नई धारा 6 में किसी राज्य के पुरुष और महिला सदस्यों के बीच सह-आंशिक संपत्ति में अधिकारों की समानता का प्रावधान है।

9-9-2005 पर और उससे संयुक्त हिंदू परिवार।

विधायिका में आसंता कुमार साहू और ओआरएस हैं। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अब उन्हें बेटियों के पक्ष में पर्याप्त अधिकार प्रदान किया गया। नई धारा 6 के अनुसार, सह-भागीदार की बेटी अपने अधिकारों और देनदारियों में जन्म से सह-भागीदार बन जाती है।

बेटे की तरह ही। धारा 6 में यह घोषणा कि सह-सहभागी की बेटी को सह-सहभागी संपत्ति में उतने ही अधिकार और देनदारियां होंगी जितनी वह एक पुत्र होती, स्पष्ट और स्पष्ट है। इस प्रकार, 9-9-2005 पर और उससे, बेटी पैतृक संपत्ति में एक हिस्से की हकदार है और एक सह-भागीदार है जैसे कि वह एक

बेटा।

12. संयुक्त संपत्ति में बेटी को उपार्जित अधिकार

मिताक्षर कानून द्वारा शासित हिंदू परिवार, 2005 के संशोधन अधिनियम के आधार पर, निरपेक्ष है, सिवाय इसके कि धारा 6 की उप-धारा (1) से जुड़े परंतुक में दी गई परिस्थितियाँ। जिन अपवादात्मक श्रेणियों के लिए 1956 के अधिनियम की नई धारा 6 लागू नहीं होती है, वे दो हैं, अर्थात् (i) जहां किसी विभाजन सहित स्वभाव या अलगाव लिया गया है।

20-12-2004 से पहले जगह; और (ii) जहां 20-12-2004 से पहले संपत्ति का वसीयती निपटान किया गया है।

धारा 6 की उप-धारा (5) संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है क्योंकि इसमें प्रावधान है कि यह धारा उस विभाजन पर लागू नहीं होगी जो 20-12-2004 से पहले प्रभावित हुआ है। के उद्देश्यों के लिए

नई धारा 6 में यह समझाया गया है कि "विभाजन" का अर्थ है पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन या अदालत के डिक्री द्वारा प्रभावित विभाजन द्वारा किया गया कोई भी विभाजन। धारा 6 की उप-धारा (5) में संलग्न स्पष्टीकरण में निहित एक स्पष्ट प्रावधान के आलोक में, धारा की गैर-प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए, यह पता लगाना प्रासंगिक है कि क्या विभाजन 20-12-2004 से पहले विधिवत विभाजन विलेख द्वारा प्रभावित किया गया है।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत या अदालत के आदेश द्वारा पंजीकृत। 1956 के अधिनियम में 2005 तक लाई गई धारा 6 के संदर्भ में उपरोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में

संशोधन अधिनियम, जिस प्रश्न का हमें उत्तर देना है, वह यह है कि क्या निचली अदालत द्वारा 19-3-1999 पर पारित और 27-9-2003 पर संशोधित प्रारंभिक डिक्री अपीलार्थियों को वंचित करती है।

2005 के संशोधन अधिनियम के लाभों के बारे में हालांकि विभाजन के लिए अंतिम आदेश अभी तक पारित नहीं किया गया है।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. कानूनी स्थिति तय की जाती है कि एक संयुक्त हिंदू का विभाजन

परिवार को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया जा सकता है, अन्य बातों के साथ-साथ, दो

ये तरीके हैं (एक) विभाजन के पंजीकृत दस्तावेज द्वारा और (दो) अदालत के आदेश द्वारा। वर्तमान मामले में,

मान लीजिए, विभाजन 20-12 से पहले प्रभावित नहीं हुआ है।
पंजीकृत साधन द्वारा या एक

2004 या तो विभाजन के

19-3-1999 दिनांकित प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से शेयरों की संख्या, जिसे 27-9-2003 पर संशोधित किया गया और की रिपोर्ट की प्राप्ति आयुक्त।

14. एक प्रारंभिक आदेश अधिकारों और हितों को निर्धारित करता है।

दलों से। विभाजन के लिए वाद का निपटान नहीं किया जाता है

प्रारंभिक डिक्री का पारित होना। यह एक अंतिम आदेश द्वारा है कि

मीट्स और बाउंड्री द्वारा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद डिक्री, मुकदमा तब तक जारी रहता है जब तक कि अंतिम डिक्री पारित नहीं हो जाती। यदि मध्यावधि में अर्थात् प्रारंभिक डिक्री के पारित होने के बाद

और अंतिम आदेश पारित होने से पहले, घटनाएँ और

पर्यवेक्षण की परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है शेयर, अदालत के लिए संशोधन करने में कोई बाधा नहीं है

प्रारंभिक डिक्री या एक और प्रारंभिक डिक्री पारित करें

पक्षों के अधिकारों और हितों का पुनर्निर्धारण करना

बदली हुई स्थिति को देखें।

60. इस प्रकार, गंडुरी कोटेश्वरम्मा (ऊपर) में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चीजें स्पष्ट कर दी हैं:

(i) सह-भागीदार की बेटी को दिया गया समान हिस्सा शासित होता है।

हिंदू मिताक्षर कानून के अनुसार भाइयों के साथ एक

मूल अधिकार;

(ii) यद्यपि मूल अधिकार 9-9-2005 पर और उससे बनाया गया है, यह जन्म की घटनाओं से संबंधित है;

(iii) मूल अधिकार केवल तभी उपलब्ध नहीं होगा जब सह-पक्षीय संपत्ति का निपटान या अलगाव किया जाता है, जिसमें 20-12-2004 से पहले संपत्ति का कोई विभाजन या वसीयती निपटान भी शामिल है।

और; (iv) यदि किसी विभाजन द्वारा सह-आंशिक संपत्ति का निपटान होता है,

ऐसा विभाजन विधिवत प्रसांत कुमार साहू और ओआरएस के विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा होना चाहिए।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत या न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावी। (v) विभाजन की प्रारंभिक डिक्री केवल पक्षों के अधिकारों और हितों को निर्धारित करती है। यह केवल एक अंतिम आदेश द्वारा है कि संयुक्त हिंदू परिवार की अचल संपत्ति को सीमा और सीमा द्वारा विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक डिक्री के पारित होने के बाद, अंतिम डिक्री पारित होने तक मुकदमा जारी रहता है। यदि मध्यावधि में अर्थात् प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद और अंतिम डिक्री पारित होने से पहले, यदि कानून में कोई परिवर्तन होता है जिसके लिए तदनुसार शेषों के निर्धारण की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय के लिए प्रारंभिक डिक्री में संशोधन करने या दोनों पक्षों के अधिकारों और हितों को पुनर्निर्धारित करने वाली एक अन्य प्रारंभिक डिक्री पारित करने में कोई बाधा नहीं होगी।

बदली हुई स्थिति को देखें।

61. विनीता शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा कानून की स्थिति का निपटारा होने से पहले इस न्यायालय के शासन करने वाले निर्णय थे।

पक्षों के अधिकार: (i) प्रकाश और अन्य बनाम। फुलावती और अन्य ने (2016) 2 एस. सी. सी. 36 और (ii) दानम्मा उर्फ सुमन सुरपुर और एक अन्य बनाम में रिपोर्ट किया। अमर और अन्य ने (2018) 3 एस. सी. सी. 343 में रिपोर्ट किया। प्रकाश (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 6 पूर्वव्यापी नहीं है और यह तब लागू होगी जब सह-भागीदार और उसकी बेटी दोनों संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख यानी 9.09.2005 पर जीवित थे। तदनुसार, धारा 6 के प्रावधानों को संभावित माना गया। दानम्मा (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 6 के संशोधित प्रावधानों ने बेटी सह-भागीदार को पूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। एक बेटी सहित कोई भी सह-भागीदार विभाजन का दावा कर सकता है

सह-स्वामित्व वाली संपत्ति।

62. दानम्मा (सुप्रा) में, एक गुरुलिंगप्पा, जो दावेदार बेटी के पिता और सह-भागीदार थे, की वर्ष 2001 में मृत्यु हो गई, जो अपने पीछे दो बेटियां, दो बेटे और एक विधवा छोड़ गए। इस प्रकार, बेटी और सह-भागीदारों के पिता जीवित नहीं थे जब प्रतिस्थापित प्रावधान था धारा 6 लागू हुई। तदनुसार, बेटियों, बेटों और विधवाओं को संपत्तियों में पांचवां हिस्सा दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जब एक बेटी, सह-पक्षीय संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करती है और मांग करती है, तो वह 9.09.2005 पर जीवित है, तो वह संशोधित प्रावधान के लाभ की हकदार होगी, भले ही इस प्रभाव की परवाह किए बिना कि किसी सह-पक्षकार की मृत्यु हो गई हो।

संशोधन अधिनियम।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

63. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रकाश (उपरोक्त) में दिए गए कथन की शुद्धता पर संदेह किया क्योंकि एक स्पष्ट संघर्ष था।

ऊपर उल्लिखित प्रकाश (ऊपर) और दानम्मा (ऊपर) में दिए गए उक्ति के बीच। अधिनियम 1956 की धारा 6 की व्याख्या से संबंधित प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

64. वृहद पीठ ने अंततः विनीता शर्मा (ऊपर) में कानून की स्थिति का निपटारा किया। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

अन्य के बीच निम्नलिखित मुख्य प्रश्नों पर विचार किया:

(i) क्या हिंदू की प्रतिस्थापित धारा 6 उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 उन मामलों में लागू होगा जहां पुरुष

सह-भागीदार की शुरुआत से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी संशोधन अधिनियम, 2005 का?

(ii) द्वारा अनुबंधित ऋणों के लिए बेटी की देयता

मृतक सह-भागीदार।

(iii) हिंदू उत्तराधिकार की प्रतिस्थापित धारा 6 की उप-धारा (5) की व्याख्या, दायरा और प्रभाव क्या है?

अधिनियम, 1956?

65. विनीता शर्मा (ऊपर) (पैरा 60,68,69 और 129) में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हिंदू की प्रतिस्थापित धारा 6 की प्रयोज्यता के लिए उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, यह आवश्यक नहीं है कि पुरुष सह-भागीदार को

संशोधन अधिनियम, 2005 (अर्थात् 9.9.2005) के प्रारंभ की तारीख को जीवित रहें। इसलिए, यह इस प्रकार है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 उन मामलों तक सीमित नहीं है जहां पुरुष

संशोधन अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद सह-भागीदार की मृत्यु हो जाती है। प्रतिस्थापित धारा 6 उन मामलों पर भी लागू होती है जहाँ पुरुष सह-भागीदार थे।

संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 66. न्यायालय ने संभावित कानून, पूर्वव्यापी कानून और पूर्वव्यापी कानून के बीच के अंतर को समझाया। यह देखा गया है कि

पैरा 61:

“ 61. संभावित क़ानून नए अधिकार प्रदान करने वाले अपने अधिनियमन की तारीख से संचालित होता है। पूर्वव्यापी क़ानून पीछे की ओर काम करता है और मौजूदा क़ानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है। एक पूर्वव्यापी क़ानून वह है जो पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करता है। यह भविष्य में काम करता है। हालाँकि, इसका संचालन उस चरित्र या स्थिति पर आधारित है जो पहले उत्पन्न हुआ था। विशेषता या घटना जो आसंता कुमार साहो और ओआरएस में हुई हो।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अतीत या आवश्यकताएँ जो पूर्ववर्ती घटनाओं से ली गई थीं। संशोधित धारा 6 के तहत, चूंकि अधिकार जन्म से दिया गया है, यानी एक पूर्व घटना, और प्रावधान अधिकार का दावा करने के संबंध में कार्य करते हैं। संशोधन अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

67. अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 6 की उप-धारा (1) की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने पैरा 60 में निम्नलिखित राय दी:

" 60. धारा 6 (1) के संशोधित प्रावधानों में यह प्रावधान है कि -

और संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से, बेटी को अधिकार प्रदान किया जाता है। धारा 6 (1) (ए) में कहा गया है -

जन्म से बेटी "अपने आप में" और "बेटे के समान तरीके से" एक सह-भागीदार है। धारा 6 (1) (ए) में मिताक्षर की अबाधित विरासत की अवधारणा शामिल है।

सह-पक्षीय संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है "जैसा कि उसे होता अगर वह एक बेटा होता"। का सम्मान अधिकार जन्म से है, और अधिकार उसी तरह से दिए जाते हैं जैसे एक बेटे की सह-भागीदारी की घटनाओं के साथ और वह है

समान अधिकारों के साथ एक सह-भागीदार के रूप में व्यवहार किया जाता है जैसे कि वह जन्म के समय एक बेटा थी। यद्यपि अधिकारों का दावा किया जा सकता है, डब्ल्यू. ई. एफ. 9-9-2005, प्रावधान पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के हैं; वे पूर्ववर्ती घटना के आधार पर लाभ प्रदान करते हैं, और मिताक्षर सह-पक्षीय कानून में एक बेटी का संदर्भ शामिल माना जाएगा।

सह-भागीदार। उसी समय, विधायिका ने प्रदान किया है

एक परंतुक जोड़कर बचत करें कि कोई भी स्वभाव या अलगाव, यदि संपत्ति या विभाजन का कोई वसीयतनामा निपटान है जो 20-12-2004 से पहले हुआ है, तो जिस तारीख को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, उसे अमान्य नहीं किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

68. न्यायालय ने पैरा 68 में आगे निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 68. सहभागीदारी के सिद्धांत पर विचार करते हुए कि एक व्यक्ति

जन्म से मिताक्षर सह-वार्षिक में अधिकार प्रदान किए जाते हैं,

इसी तरह, बेटी को मान्यता दी गई है और एक बेटे के समान अधिकारों और देनदारियों के साथ एक सह-भागीदार के रूप में माना गया है। धारा 6 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति यह है कि वह [2023] 5 एस. सी. आर. बन जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक बेटे के रूप में उसी तरह सह-भागीदार। गोद लेने से भी सह-भागीदार का दर्जा दिया जा सकता है। की अवधारणा

अबाधित विरासत का संहिताबद्ध हिंदू कानून दिया गया है।

धारा 6 (1) (ए) और 6 (1) (बी) के प्रावधानों के तहत एक ठोस आकार। सह-भागीदार का अधिकार जन्म से है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है।

आवश्यक है कि बेटी के पिता के रूप में जीवित होना चाहिए

संशोधन की तारीख को, क्योंकि उन्हें सम्मानित नहीं किया गया है

बाधित विरासत द्वारा सह-भागीदार के अधिकार। के अनुसार मिताक्षर सह-पक्षीय हिंदू कानून, जैसा कि प्रशासित है

जो धारा 6 (1) में मान्यता प्राप्त है, यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन की तारीख को कोई जीवित, सह-भागीदार या पिता होना चाहिए जिसके लिए बेटी उत्तराधिकारी होगी। बेटी अधिनियम से पहले या बाद में जन्म लेकर बेटे के रूप में सह-अधिवेशन में कदम रखेगी। हालाँकि, पहले पैदा हुई बेटी इन अधिकारों का दावा केवल संशोधन की तारीख से ही कर सकती है, अर्थात् धारा 6 (1) के प्रावधान में दिए गए पिछले लेनदेन की बचत के साथ, जिसे धारा के साथ पढ़ा जाता है।

6 (5) . " (जोर दिया गया) 69. न्यायालय ने पैरा 69 में आगे कहा है:

" 69. धारा 6 (1) संयुक्त रूप से शासित हिंदू परिवार को मान्यता देती है।

सह-भागीदार की बेटी को अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए उसे दिया। चूंकि अधिकार जन्म से है और विरासत से नहीं, इसलिए यह अप्रासंगिक है कि एक सह-भागीदार जिसकी बेटी हो।

अधिकार दिए गए हैं जो जीवित हैं या नहीं। कन्फेरल नहीं है

पिता या अन्य सह-भागीदार की मृत्यु पर आधारित। मामले में

9-9-2005 के बाद जीवित सह-भागीदार की मृत्यु हो जाती है, विरासत द्वारा नहीं उत्तरजीविता लेकिन निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार द्वारा

प्रतिस्थापित धारा 6 (3) में उपबंधित। " (जोर दिया गया)

70. प्रतिस्थापित धारा 6 की उप-धारा (3) को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने पैराग्राफ 66 में कहा:

" 66. संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद मरने वाले हिंदू के संबंध में, जैसा कि धारा 6 (3) में प्रावधान किया गया है, उसका हित वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा पारित होगा, न कि उत्तरजीविता, और वहाँ का एक माना विभाजन है

शेयरों का पता लगाने के लिए सह-आंशिक संपत्ति जो

उनके उत्तराधिकारियों को आवंटित किया जाता अगर कोई आसांत कुमार साहू और ओआरएस होता।

बी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विभाजन। बेटी को एक के समान हिस्सा आवंटित किया जाना है

बेटा; यहाँ तक कि पूर्व मृत बेटी या बेटे का जीवित बच्चा

यदि बच्चे की भी मृत्यु हो गई है तो उसे एक हिस्सा दिया जाता है

ऐसे पूर्व-मृत बच्चे का जीवित बच्चा

बेटे या पूर्व-मृत बेटी को समान हिस्सा आवंटित किया जाता, अगर वे विभाजन के समय जीवित होते। इस प्रकार, प्रतिस्थापित धारा 6 में एक समुद्री परिवर्तन है। मृत्यु के मामले में

9-9-2005 के बाद सह-सहभागी का, उत्तराधिकार द्वारा नहीं है

उत्तरजीविता लेकिन धारा 6 (3) के अनुसार। द.

धारा 6 (3) का स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण। के समान है।

धारा 6 जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था। (जोर दिया गया)

71. निम्नलिखित प्रस्ताव, अन्य के अलावा, विनीता शर्मा (ऊपर) में निर्णय के समान पैराग्राफ से आते हैं:

(ए) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 की उप-धारा (1) एक संयुक्त हिंदू परिवार को शासित मानता है। मितक्षर कानून द्वारा।

(बी) सह-सहभागी 9.9.2005 पर मौजूद होना चाहिए, यानी, की तारीख

संशोधन अधिनियम, 2005 का प्रारंभ। ((ग) बेटी को जन्म से ही बेटे के समान अधिकार और देनदारियों के साथ सह-भागीदार के रूप में पहचाना और माना गया है।

((घ) यह आवश्यक नहीं है कि एक सह-भागीदार जिसकी बेटी को अधिकार प्रदान किए गए हैं, जीवित हो या नहीं।

संशोधन अधिनियम, 2005 का प्रारंभ। बेटी होगी।

जन्म से एक बेटे के रूप में सह-पक्ष में कदम रखें।
रखेगी

(ई) हालांकि बेटी सह-अधिवेशन में कदम

संशोधन अधिनियम, 2005 का प्रारंभ या उसके बाद संशोधन अधिनियम, 2005 का प्रारंभ,
लेकिन संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले पैदा हुई बेटी केवल निम्नलिखित तिथि से सह-आंशिक
अधिकारों का दावा कर सकती है -

संशोधन, अर्थात्, धारा 6 (5) के साथ पठित धारा 6 (1) के परंतुक में दिए गए पिछले लेन-देनों की
बचत के साथ।

(च) यदि संशोधन अधिनियम, 2005 (अर्थात 9.9.2005) के प्रारंभ की तारीख को रहने वाले किसी सह-भागीदार की मृत्यु 9.9.2005 के बाद हो जाती है, तो विरासत उत्तरजीविता द्वारा नहीं बल्कि निर्वसीयत या वसीयतनामा द्वारा होती है।

प्रतिस्थापित धारा 6 (3) में दिए गए अनुसार उत्तराधिकार।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

72. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संविधान की प्रतिस्थापित धारा 6 की उप-धारा (5)

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में प्रावधान किया गया है कि प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित कुछ भी विभाजन पर लागू नहीं होगा, जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले प्रभावी हो गया है (यानी जिस तारीख को संशोधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था)। प्रतिस्थापित धारा 6 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि धारा 6 के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" का अर्थ है (i) पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन, या (ii) अदालत की डिक्री द्वारा प्रभावित कोई विभाजन। प्रतिस्थापित धारा 6 की उप-धारा (5) की व्याख्या करते हुए और प्रतिस्थापित धारा 6 के लिए स्पष्टीकरण देते हुए, विनीता शर्मा (ऊपर) मामले में न्यायालय ने पैरा 67 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" 67. धारा 6 (1) और धारा 6 (5) का परंतुक किसी भी प्रावधान को बचाता है।

20-12-2004 से पहले प्रभावित विभाजन। हालांकि, स्पष्टीकरण

धारा 6 (5) के निष्पादन द्वारा प्रभावित विभाजन को मान्यता देता है पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन का एक विलेख,

1908 या किसी अदालत के आदेश द्वारा। विभाजन के अन्य रूप हैं

में "विभाजन" की परिभाषा के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है स्पष्टीकरण।

73. प्रतिस्थापित धारा 6 की उप-धारा (5) के संबंध में और

प्रतिस्थापित धारा 6 के स्पष्टीकरण में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

(ए) यह माना गया है कि बेटी अब हकदार हो गई है

9.09.2005 से प्रभाव के साथ सह-विभाजन का दावा करें जैसे कि बेटा।

न्यायालय ने पैरा 85 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 85. विभाजन का दावा करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है।

सह-भागीदार का, और एक सह-भागीदार वह है जो दावा कर सकता है विभाजन। बेटी अब दावा करने की हकदार हो गई है।

सह-पक्षीय डब्ल्यू. ई. एफ. 9-9-2005 का विभाजन, जो एक महत्वपूर्ण है
कानून द्वारा लाया गया परिवर्तन। एक सह-भागीदार आनंद लेता है
स्थिति के विच्छेद की मांग करने का अधिकार। धारा 6 (1) के तहत
और 6 (2), एक बेटी के अधिकार एक बेटे के साथ समान हैं।
विभाजन की संभावना में, पुत्रों और पुत्रों के अलावा
बेटियाँ, सह-भागीदार की पत्नी भी एक का हकदार है
बराबर हिस्सेदारी। सह-भागीदार की पत्नी का दावा करने का अधिकार
संपत्ति में उसका अधिकार किसी भी तरह से नहीं खोया जाता है।

(जोर दिया

गया)

आसंता कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(ख) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विभाजन से संबंधित कानून के तहत संशोधन अधिनियम, 2005 से पहले, यदि पिता (एफ) और पुत्रों (एस 1 और एस 2) के बीच सह-आंशिक संपत्ति का विभाजन होगा।

तब पिता (एफ) की पत्नी (डब्ल्यू) के साथ-साथ पिता (एफ) की विधवा माँ (एम) को एक बेटे (एस 1 या एस 2) के बराबर हिस्सा मिलेगा। यह स्थिति बनी हुई है जैसा कि इस न्यायालय के निर्णय के उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ 85 के अंतिम भाग में किए गए अवलोकन से स्पष्ट है। इसलिए, यदि कोई विभाजन है

पिता और पुत्रों के बीच सह-आंशिक संपत्ति (और अब भी) बेटियाँ), तब पिता की पत्नी के साथ-साथ पिता की विधवा माँ को एक बेटे (या एक बेटे) के बराबर हिस्सा मिलेगा।

(ग) मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के तहत, एक संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य परिवार से खुद को अलग करने और कई में अपने हिस्से का आनंद लेने के अपने इरादे की एक निश्चित, स्पष्ट और एकतरफा घोषणा करके अपनी अलग स्थिति ला सकता है। इस प्रकार, एक संयुक्त परिवार के सदस्य द्वारा विभाजन के लिए एक मुकदमे की स्थापना अलग होने के उनके इरादे की एक स्पष्ट सूचना है, और वहाँ था

संयुक्तता की स्थिति का परिणामी विच्छेद। विनीता शर्मा (ऊपर) में इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न था: विभाजन वाद के लंबित रहने के दौरान या विभाजन वाद में प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के पारित होने के बीच की अवधि के दौरान, कोई विधायी संशोधन या कोई वाद की घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप पक्षों के शेयरों का विस्तार या कमी या उनके अधिकारों में परिवर्तन होता है, चाहे ऐसा विधायी संशोधन या वाद की घटना विभाजन वाद में अंतिम डिक्री पारित करते समय विचार में रखी जा सकती है और प्रभावी की जा सकती है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही विभाजन वाद दायर करने से संयुक्तता की स्थिति अलग हो जाती है, लेकिन इस तरह के विधायी संशोधन या वाद की घटना को ध्यान में रखा जाना चाहिए और विभाजन वाद में अंतिम डिक्री पारित करने में प्रभावी होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभाजन मुकदमे को पूरी तरह से और पूरी तरह से तभी तय किया जा सकता है जब अंतिम डिक्री पारित हो जाए। यह एक अंतिम आदेश द्वारा है कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का विभाजन सीमा और सीमा के अनुसार होता है।

(पैराग्राफ 89 से 102 और पैराग्राफ 106,114,133 और 136 देखें। न्यायालय ने पैरा 107 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 107. एक बार जब सह-सदस्य का संविधान बदल जाता है

जन्म या मृत्यु, शेयरों पर उस समय काम करना होगा जब

परिदृश्य बदल गया। स्थिति का विच्छेद नहीं आ सकता है
वैधानिक प्रावधान और परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए

बाद की घटना से। विभाजन की वैधानिक कल्पना है

वास्तविक विभाजन से बहुत कम, यह नहीं लाता है

संयुक्त परिवार या सहभागीदारी में व्यवधान एक है

कानून का तय प्रस्ताव। उल्लिखित कारणों से

ऊपर, हमारी यह भी राय है कि केवल विच्छेद

मुकदमा दायर करने के माध्यम से स्थिति नहीं लाती है

विभाजन और अंतिम डिक्री की तारीख तक, में परिवर्तन

कानून, और बाद की घटना के कारण परिवर्तन किए जा सकते हैं

(जोर दिया

गया)

विचार में "।

(डी) संशोधन अधिनियम, 2005 से पहले, संयुक्त हिंदू में विभाजन

परिवार मौखिक विभाजन या मौखिक पारिवारिक समझौते द्वारा बनाया जा सकता है /

पारिवारिक व्यवस्था। यदि बाद में इस तरह के मौखिक विभाजन की शर्तें
या मौखिक पारिवारिक निपटान/पारिवारिक व्यवस्था दर्ज की जा सकती है।

एक ज्ञापन में। इस तरह के ज्ञापन की आवश्यकता नहीं थी

पंजीकृत। [देखिए: पैराग्राफ 115,116,119,120,121,125 और 130]।

74. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिस्थापित धारा 6 के स्पष्टीकरण में प्रावधान है

कि धारा 6 "विभाजन" के प्रयोजनों के लिए इसका अर्थ है (i) पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन, या (ii) किसी
न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावित कोई विभाजन। न्यायालय ने आगे के प्रभाव पर विचार किया

20 दिसंबर, 2004 से पहले किए गए मौखिक विभाजन या मौखिक पारिवारिक निपटान/पारिवारिक व्यवस्था पर उपरोक्त स्पष्टीकरण। न्यायालय ने पैरा 124 में निम्नलिखित राय दी:

" 124. संशोधित धारा 6 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

बेटियाँ हिस्सेदारी प्राप्त करने के अपने अधिकारों से वंचित नहीं हैं

सह-भागीदार बनने और विभाजन का दावा करने पर तुच्छ रक्षा की स्थापना करके सह-आंशिक संपत्ति

मौखिक विभाजन और/या अपंजीकृत में दर्ज किया गया

विभाजन का ज्ञापन। अदालत को ध्यान रखना होगा कि

संभावना है कि मौखिक विभाजन का एक अनुरोध स्थापित किया जा सकता है,

धोखाधड़ी से या मिलीभगत से, या अपंजीकृत के आधार पर

विभाजन का ज्ञापन जो किसी भी आसांत कुमार सहू और ओ. आर. एस. में भी बनाया जा सकता है।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

समय का बिंदु। ऐसा विभाजन धारा 6 (5) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

(जोर दिया गया)

75. न्यायालय ने आगे पैरा 135 को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 135. विभाजन की एक विशेष परिभाषा में तराशी गई है

स्पष्टीकरण। प्रावधानों का उद्देश्य बेटी के हित को खतरे में डालना और बेटी को सह-भागीदार के रूप में उसके अधिकार से वंचित करने के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से रक्षा में स्थापित नकली या तुच्छ लेनदेन का ध्यान रखना और प्रावधानों से प्राप्त लाभ को रद्द करने से रोकना नहीं है।

प्रतिस्थापित। धारा 6 (5) में बनाए गए वैधानिक प्रावधान विभाजन के रूप में पूरे रंग को बदल देते हैं। हालाँकि, पहले प्रचलित कानून के तहत, एक मौखिक विभाजन को मान्यता दी गई थी। धारा 6 के प्रावधानों के परिवर्तन को देखते हुए, विधायिका का इरादा स्पष्ट है और मौखिक विभाजन की ऐसी याचिका को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। धारा 6 (5) के प्रावधान हैं:

सबूत का भारी बोझ डालने के लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है

मौखिक विभाजन के प्रस्तावक पर इसे स्वीकार करने से पहले जैसे कि भागों का अलग कब्जा, आय का विनियोग, और राजस्व अभिलेखों में परिणामी प्रविष्टि और

हमेशा अन्य समकालीन जनता द्वारा समर्थित होना

साक्ष्य में स्वीकार्य दस्तावेजों को सभी सुरक्षा उपायों का प्रयोग करते हुए सबसे अनिच्छा से स्वीकार किया जा सकता है। इरादा. अधिनियम की धारा 6 केवल उन वास्तविक विभाजनों को स्वीकार करने के लिए है जो प्रचलित कानून के तहत हो सकते हैं, और हैं

एक झूठे बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है और केवल मौखिक इप्स डिक्स्ट को पूरी तरह से अस्वीकार किया जाना है। लाभ को शून्य करने के लिए झूठे या तुच्छ बचाव को रोकने, स्थापित करने का उद्देश्य

संशोधित प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा बेटी को वंचित करना बहुत आसान हो जाता।

एक सह-भागीदार के रूप में उसके अधिकारों का। जब इस तरह का बचाव किया जाता है, तो अदालत को इसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है, और केवल तभी जब बहुत ठोस, त्रुटिहीन, और जनता के रूप में समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य

समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध हैं, इस तरह की याचिका पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हम दोहराते हैं कि एक की याचिका

मौखिक विभाजन या विभाजन का ज्ञापन, अपंजीकृत

किसी भी समय निर्मित किया जा सकता है, बिना किसी समकालीन सार्वजनिक दस्तावेज़ को अस्वीकार करने की आवश्यकता है [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लागते। हम ऐसा असाधारण रूप से अच्छे मामलों के लिए कहते हैं जहाँ विभाजन होता है।

निर्णायक रूप से साबित होता है और हम अदालतों को आगाह करते हैं कि

खोज की प्रधानता पर आधारित नहीं होना चाहिए

लैंगिक न्याय के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संभावनाएँ और

सबूत का बहुत भारी बोझ जो धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण के इरादे को पूरा करता है। यह याद रखना होगा कि अदालतें संशोधन अधिनियम द्वारा बनाए गए लाभकारी प्रावधानों के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती हैं। विभाजन के लिए एक पंजीकृत दस्तावेज़ के पूर्व निष्पादन के रूप में अपवाद हमारे द्वारा बनाया गया है।

यह आवश्यक नहीं था, और पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए शायद ही कभी अदालत से संपर्क किया जाता था। इसे अंतिम उपाय के रूप में लिया गया था

जब पक्ष अपने पारिवारिक विवाद को निपटाने में सक्षम नहीं थे

सौहार्दपूर्ण ढंग से। हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि 1956 से पहले भी, धारा 6 (5) के तहत परिकल्पित अन्य तरीकों से विभाजन हुआ था। (जोर दिया गया)। (संदर्भ: न्यायमूर्ति सत्य पूत मेहरोत्रा, पूर्व न्यायाधीश द्वारा 'हिंदू कॉपरसेनरी के बदलते आयाम और धारा 6, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' शीर्षक वाला लेख

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश)

76. अंत में संदर्भ का उत्तर पैरा 137.1 से 137.5 y में नीचे दिया गया था:

“ 137.1 . हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित प्रावधान सह-भागीदार का दर्जा प्रदान करते हैं।

संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई बेटी पर

समान अधिकार और देनदारियों वाले बेटे के समान।

137.2 . धारा में दी गई बचत के साथ 9-9-2005 से पहले पैदा हुई बेटी द्वारा अधिकारों का दावा किया जा सकता है।

6 (1) स्वभाव या अलगाव, विभाजन या

वसीयती स्वभाव जो इससे पहले हुआ था

20 दिसंबर, 2004 का पहला दिन।

137.3 . चूँकि सहभागीदारी में अधिकार जन्म से है, इसलिए यह नहीं है

यह आवश्यक है कि पिता सह-भागीदार 9 से 9 तक जीवित रहें

2005 .

137.4 . मूल रूप से अधिनियमित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधान द्वारा बनाए गए विभाजन की वैधानिक कल्पना ने वास्तविक विभाजन या व्यवधान पैदा नहीं किया।

सह-पक्षीय। कल्पना केवल इस उद्देश्य के लिए थी कि

मृत सह-भागीदार के हिस्से का पता लगाना जब वह आसांत कुमार साहू और ओआरएस थे।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वर्ग I की एक महिला उत्तराधिकारी द्वारा जीवित, जैसा कि में निर्दिष्ट है

1956 के अधिनियम की अनुसूची या ऐसी महिला का पुरुष रिश्तेदार। प्रतिस्थापित धारा 6 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से प्रभावी किए जाने की आवश्यकता है। इसके बावजूद कि एक प्रारंभिक आदेश दिया गया है

पारित होने पर, अंतिम डिक्री या अपील के लिए लंबित कार्यवाही में बेटियों को बेटे के बराबर भागीदारी में हिस्सा दिया जाना है।

137.5 . 1956 के अधिनियम की धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों की कठोरता को देखते हुए मौखिक विभाजन की याचिका दायर नहीं की जा सकती है।

विभाजन के वैधानिक मान्यता प्राप्त तरीके के रूप में स्वीकार किया जाए के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन के विलेख द्वारा प्रभावित

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधान या किसी न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावी। हालांकि, अपवादात्मक मामलों में जहां मौखिक याचिका दायर की जाती है

विभाजन सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित है और विभाजन है

अंत में उसी तरीके से प्रकट किया जाता है जैसे कि यह किसी अदालत की डिक्री से प्रभावित (एस. आई. सी. प्रभावित) हुआ हो, इसे स्वीकार किया जा सकता है। ए.

केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन का अनुरोध नहीं किया जा सकता है

स्वीकार किया जाता है और पूरी तरह से अस्वीकार किया जाता है।

77. विनीता शर्मा (ऊपर) का निर्णय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि अपील के लंबित रहने के दौरान एक जी. ई. इन लॉ पर विचार किया जाना चाहिए और इसे प्राथमिकता से लागू किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर बनाम पर भरोसा किया। अभिजीत टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने 000) 7 एससीसी 357 की सूचना दी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

" 20. अब, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह अदालत का कर्तव्य है, चाहे वह मूल कार्यवाही की सुनवाई कर रहा हो या किसी अपील की सुनवाई कर रहा हो।

लंबित कार्यों को प्रभावित करने वाले कानून में परिवर्तन की सूचना और उसे प्रभावी बनाने के लिए। (जी. पी. सिंह को देखिए: कानूनों की व्याख्या, 7 वीं संस्करण।, पी। 406.) यदि, जब कोई मुकदमा लंबित है, 1993 के अधिनियम जैसा कानून पारित किया जाता है कि दीवानी अदालत मुकदमे का फैसला नहीं करेगी, तो दीवानी अदालत न्यायिक नोटिस लेने के लिए बाध्य है

कानून और अभिनिर्धारित करता है कि मुकदमा उसके रिमांड के बाद भी

इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है "।

78. विनीता शर्मा (ऊपर) मामले में इस अदालत ने पूरे मामले को स्पष्ट किया।

इस प्रकार है:

" 107. एक बार जन्म से सह-विभाजन का संविधान बदल जाता है

या मृत्यु, शेयरों को वास्तविक विभाजन के समय तैयार किया जाना चाहिए। शेयरों का निर्धारण परिवर्तित (2023) 5 एस. सी. आर. में करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिदृश्य। स्थिति का विच्छेद रास्ते में नहीं आ सकता है
वैधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाना और बाद में परिवर्तन करना।

घटना। विभाजन की वैधानिक कल्पना वास्तविक से बहुत कम है।

विभाजन, यह संयुक्त का व्यवधान नहीं लाता है

परिवार या सह-सदस्य का प्रस्ताव कानून का एक तय प्रस्ताव है।

ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी भी राय है

कि केवल मुकदमा दायर करने के माध्यम से स्थिति का अलगाव नहीं है

विभाजन के बारे में और अंतिम डिक्री की तारीख तक,
कानून में परिवर्तन, और बाद की घटना के कारण परिवर्तन हो सकते हैं

ध्यान में रखा जाए।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

114. तत्काल मामले में, सवाल अलग है। क्या है?

धारा के तहत कानून द्वारा विभाजन के रूप में मान्यता दी गई

6 , तदनुसार, अधिकारों पर काम किया जाना है। यह न्यायालय

ऊपर वर्णित विभिन्न निर्णयों में लगातार आयोजित किया गया कि

प्रदान किया गया। इसलिए, हमें प्रभाव को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है
धारा 6 के परंतुक की वैधानिक कल्पना, जैसा कि चर्चा की गई है

प्रकाश वी. फुलावती [(2016) 2 एससीसी 36: (2016) 1 एससीसी

संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख, वह एक बन जाती है
संशोधन अधिनियम की तारीख से प्रभावी सह-भागीदार,

समय से पहले जन्म तिथि चाहे जो भी हो।

के विदेशी सिद्धांतों का अनुप्रयोग

वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए कानून

79. आइए हम इस समय के लिए मान लें कि निचली अदालत

वादी के पक्ष में वाद का फैसला किया है, यानी बेटी ने पैतृक संपत्ति सहित सभी संपत्तियों में अपना एक तिहाई हिस्सा समान रूप से दिया है।

संपत्तियाँ। यह तर्क दिया जा सकता था कि निचली अदालत प्रासंगिक समय पर प्रचलित कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं कर सकती थी। तथापि, विनीता शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद अंश का ऐसा आवंटन कानून के अनुसार होगा। आइए हम एक दूसरे विकल्प को भी मान लें। उदाहरण के लिए, निचली अदालत ने (i) स्व-अर्जित संपत्ति में बेटी को एक तिहाई हिस्सा देने और (ii) आधे प्रशांत कुमार साहो और ओ. आर. एस. में एक तिहाई हिस्सा देने का फैसला किया होगा।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

पैतृक संपत्ति में पिता का हिस्सा था। यह था कानून प्रासंगिक समय पर प्रचलित है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई प्रारंभिक डिक्री को पारित करते हुए, वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने ठीक यही किया है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अब कानून बदल गया है।

80. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि बेटियाँ शिकायत में निर्धारित सभी संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से की हकदार हैं। वैसा ही।

विनीता शर्मा के कथन के अनुसार होगा।

(ऊपर), अंतिम डिक्री पारित करते समय। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम कहते हैं कि निचली अदालत द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री के आधार पर, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने की थी, उसमें तय किए गए मुद्दों को अंतिम माना जाएगा, लेकिन विभाजन मुकदमे का निर्णय चरणों में किया जाना आवश्यक है, इसे पूरी तरह से और पूरी तरह से अंतिम डिक्री पारित होने पर ही तय किया जा सकता है। चूंकि अंतिम डिक्री कार्यवाही के समापन से पहले पक्षों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन किया गया है, इसलिए इस तरह के संशोधन से लाभान्वित होने वाला पक्ष (मामले में दो बेटियों की तरह) ट्रायल कोर्ट से संशोधन का संज्ञान लेने और इसे प्रभावी बनाने का अनुरोध कर सकता है।

एक ही।

पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले कानून के संशोधन के बावजूद कार्यवाही। 82. हमारी राय में, कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है, यह निर्धारित करते समय नीचे दिए गए न्यायालयों पर की गई है।

दलों के शेयर। अब केवल 1956 के अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों में संशोधन को प्रभावी बनाने और तदनुसार पक्षों के शेयरों का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता है। इसे रखने के लिए

सीधे तौर पर, वादी अपने दिवंगत पिता की सभी संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से का हकदार है। यह मुद्दा कि क्या सभी संपत्तियां पैतृक थीं, जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से उठाया गया था, महत्वहीन हो जाता है।

इश्यू नं। 2

83. अब हम इस मुद्दे संख्या 2 का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या उच्च न्यायालय मूल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रति-अपील को इस आधार पर स्वीकार करने में उचित था कि अपीलकर्ताओं (प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2) के बीच हुआ समझौता सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 3 के तहत वैध और बाध्यकारी नहीं था।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84. श्री बसंत, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 और उसकी बहन यानी प्रतिवादी संख्या 2 के बीच समझौते पर 29.03.1991 पर हलफनामे पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता उच्च न्यायालय द्वारा पहली अपील की अंतिम सुनवाई के समय 9.04.1991 पर रिकॉर्ड पर लिया गया था। पहली अपील का निपटारा 1.08.2000 पर किया गया, जिसमें दोनों प्रतिवादियों के बीच समझौते की शर्तों को शामिल करने की सीमा तक डिक्री में संशोधन किया गया। यह दस साल के अंतराल के बाद ही है कि अपीलार्थियों द्वारा डिवीजन के समक्ष दायर अपील के लंबित रहने के दौरान

उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कथित समझौते को चुनौती देते हुए प्रति-अपील दायर करना उचित समझा। श्री बसंत ने प्रस्तुत किया

कि ऐसी प्रति-अपील विचारणीय नहीं है और भले ही इसे विचारणीय माना गया हो, लेकिन समझौता दर्ज करने की तारीख से लगभग दस साल के अंतराल के बाद भी इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

85. हम श्री बसंत की उपरोक्त दलीलों से बहुत प्रभावित नहीं हैं। यह कानून की एक तय स्थिति है कि अपील का अधिकार है कानून का सृजन। अपील करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। जब तक कानून अपीलार्थी को अधिकार और न्यायालय को ऐसा करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है, तब तक कोई भी अपील गुण-दोष के आधार पर दायर, सुनी या निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस स्तर पर हम सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 के प्रावधानों पर गौर कर सकते हैं:

" 22. सुनने पर प्रत्यर्थी डिक्री पर आपत्ति कर सकता है जैसे कि उसने एक अलग अपील को प्राथमिकता दी हो। - (1) कोई भी प्रत्यर्थी, हालांकि उसने डिक्री के किसी भी हिस्से से अपील नहीं की होगी, न केवल डिक्री का समर्थन कर सकता है [बल्कि यह भी कह सकता है कि निष्कर्ष

किसी भी मुद्दे के संबंध में नीचे दिए गए न्यायालय में उसके खिलाफ उसके पक्ष में होना चाहिए था; और वह उस डिक्री पर कोई भी प्रति-आपत्ति भी ले सकता है जिसे वह अपील के माध्यम से ले सकता था, बशर्ते कि उसने अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन की सेवा की तारीख से एक महीने के भीतर या ऐसे आगे के समय के भीतर अपीलीय न्यायालय में ऐसी आपत्ति दायर की हो जिसे अपीलीय न्यायालय उचित समझे।

अनुमति दें।

[स्पष्टीकरण। न्यायालय के उस निर्णय के निष्कर्ष से व्यथित कोई प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध अपील की गई डिक्री आधारित है, इस नियम के तहत डिक्री के संबंध में जहां तक वह उस निष्कर्ष पर आधारित है, प्रति-आपत्ति दायर कर सकता है।

इसके बावजूद अदालत के फैसले के कारण A. S. A. N. T. K. M. A. S. H. O & O. R. S.

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उत्तरदाता।] (2) आपत्ति का रूप और उस पर लागू प्रावधान। —

ऐसी प्रति-आपत्ति एक ज्ञापन के रूप में होगी,

और नियम 1 के प्रावधान, जहाँ तक वे प्रपत्र से संबंधित हैं

और अपील के ज्ञापन की सामग्री लागू होगी।

वहाँ तक। [3 ***]

(4) जहाँ, किसी भी मामले में जिसमें किसी भी प्रतिवादी के अधीन है

इस नियम ने एक आपत्ति ज्ञापन दायर किया, मूल अपील

वापस ले लिया जाता है या डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया जाता है, इस प्रकार आपत्ति दायर की जाती है

फिर भी ऐसी सूचना के बाद सुना और निर्धारित किया जा सकता है अन्य पक्षों के लिए जैसा कि न्यायालय उचित समझता है।

(5) निर्धन व्यक्तियों की अपीलों से संबंधित प्रावधान

जहाँ तक उन्हें लागू किया जा सकता है, एक पर लागू होगा इस नियम के तहत आपत्ति "।

86. क्रॉस-ऑब्जेक्शन को प्राथमिकता देने का अधिकार अधिकार का हिस्सा है

आर एक अपील। प्रतिवादी नं. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

इसमें स्पष्ट संख्या 2) कि आदेश XLI नियम के तहत एक प्रति-अपील

सी. पी. सी. एक नियमित पहली अपील के रूप में प्रभावी है और वही

घ स्थायी, भले ही, नियमित पहली अपील खारिज या वापस ले ली गई हो।

एस. एस.-अपील अपील के मूल अधिकार का प्रयोग है और केवल

स्वभाव अलग-अलग होता है। (देखिए: उर्मिला देवी और अन्य बनाम। शाखा प्रबंधक,

जोनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर, (2020) 11 एस. सी. सी.

पैरा 16.)

87. हमारा ध्यान आदेश XLIII के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया गया था

ले 1-सी. पी. सी. का ए (2)। वही नीचे पढ़ा गया है:

" 1 ए. अपील में गैर-अपील योग्य आदेशों को चुनौती देने का अधिकार

आदेशों के खिलाफ। —

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

(2) बाद में एक मुकदमे में पारित एक डिक्री के खिलाफ अपील में
समझौता दर्ज करना या समझौता दर्ज करने से इनकार करना,
यह अपीलार्थी के लिए डिक्री को चुनौती देने के लिए खुला होगा
इस आधार पर कि समझौता होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था

किया गया। "[2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

89. उपरोक्त संदर्भ में, हम बनवारी लाल बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। चंदो देवी (श्रीमती) और एक अन्य (1993) 1 एस. सी. सी. 581 में अधिक विशेष रूप से, पैरा 9 से 13 में उत्तर दिया गया है:

" 9. संहिता की धारा 96 (3) में कहा गया है कि पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। नियम 1-ए (2) को यह कहते हुए पेश किया गया है कि समझौता दर्ज करने के बाद मुकदमे में पारित डिक्री के खिलाफ, यह

अपीलार्थी इस आधार पर डिक्री का विरोध करने के लिए खुला रहेगा कि समझौता दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। जब धारा 96 (3) पारित डिक्री के खिलाफ अपील को रोकती है

पक्षों की सहमति से, इसका तात्पर्य है कि ऐसी डिक्री पार्टियों पर वैध और बाध्यकारी है जब तक कि पार्टियों के लिए निर्धारित या उपलब्ध प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जाता है। ऐसा ही एक उपलब्ध उपाय आदेश 43, नियम 1 (एम) के तहत अपील दायर करना था। यदि समझौते को दर्ज करने वाले आदेश को अलग कर दिया गया था, तो वहाँ

डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने की कोई आवश्यकता या अवसर नहीं था। इसी तरह इस तरह की डिक्री को इस आधार पर खारिज करने के लिए एक मुकदमा दायर किया जाता था कि डिक्री एक अमान्य और अवैध समझौते पर आधारित है जो दूसरे मुकदमे के वादी पर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जो संशोधन पेश किए गए हैं, उनके बाद आदेश 23 के नियम 3-ए के दायरे में आने वाले मामलों में न तो समझौता दर्ज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील और न ही मुकदमा दायर करने का उपाय उपलब्ध है। जैसा कि आदेश 43 के नियम 1-ए (2) के तहत एक पक्ष को अधिकार दिया गया है, जो समझौते की रिकॉर्डिंग को चुनौती देता है, डिक्री के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाता है। संहिता की धारा 96 (3) ऐसी अपील के लिए बाधा नहीं होगी। क्योंकि धारा 96 (3) उन मामलों में लागू होती है जहां समझौते या समझौते का तथ्य विवाद में नहीं है।

10. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने एक

यह स्थिति कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण आसंता कुमार साहू और ओ. आर. एस. लेना उचित था।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कि वादी अपीलार्थी द्वारा आदेश 23 के नियम 1 के तहत मुकदमा केवल वापस ले लिया गया था और यह नहीं किया गया था उक्त आदेश 23 के नियम 3 के संदर्भ में समझौता; जैसे कि

अपीलार्थी के लिए उक्त आदेश को वापस लेने और योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए विचाराधीन मुकदमे को बहाल करने के लिए आवेदन दायर करने का कोई अवसर नहीं था। 27 फरवरी, 1991 को दायर की गई याचिका की प्रति से ऐसा प्रतीत होता है कि

समझौते और समझौते के नियम और शर्तें थीं

यह उल्लेख करते हुए कि दोनों पक्षों ने एक समझौता किया था जिसके कारण वादी-अपीलार्थी का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं था और

अदालत ने आदेश 23 के नियम 1 के संदर्भ में मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दी। इसके बावजूद आदेश का उद्देश्य समझौता याचिका में उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर वादी के मुकदमे को खारिज करना था। इस प्रकार, उस आदेश की वैधता का निर्णय यह मानते हुए किया जाना चाहिए कि यह एक ऐसा आदेश है जिसे संहिता के आदेश 23 के नियम 3 द्वारा न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग में पारित किया गया है। विद्वत अधीनस्थ न्यायाधीश को समझौते की उक्त याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, भले ही उसे अपीलार्थी पर उसके वकील द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के बारे में कोई जानकारी न हो, क्योंकि स्वीकार किया जाता है कि समझौते की याचिका को स्वीकार नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित। इस तथ्य का पता अदालत को लगाना चाहिए था। गुरप्रीत के मामले में

सिंह बनाम। चतुर भुज गोयल [(1988) 1 एससीसी 270: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 400] यह कहा गया है: (एस. सी. सी पी. 276, पैरा 10) “ नियम 3 के तहत जैसा कि अब है, जब मुकदमे में किसी दावे को किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, तो समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और एक पूर्ण समझौता [2023] 5 एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी वाद या अपील की सुनवाई, इसका कोई कारण नहीं है कि यह आवश्यकता कि समझौते को पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के रूप में लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए, को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए अदालत को पक्षों पर लिखित रूप में शर्तों को कम करने के लिए जोर देना चाहिए।

संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की याचिका की आवश्यकता पर भी बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम के मामले में विचार किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [(1992) 1 एस. सी. सी. 31: ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2234] ऐसा प्रतीत होता है कि गुरप्रीत सिंह बनाम में इस न्यायालय के उपरोक्त मामले की ओर विद्वान न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था। चतुर भुज गोयल [(1988) 1 एससीसी 270: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 400]

11. वर्तमान मामला दर्शाता है कि कैसे 27 फरवरी, 1991 को अदालत ने कथित समझौते और समझौते को दर्ज किया।

एक आकस्मिक तरीके से। यह प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है कि आदेश 23 के नियम 3 में किसी कथित समझौते या समझौते के लिए अदालत से केवल अनुमोदन की मुहर की आवश्यकता नहीं है। दलों के बीच प्रवेश किया। कानून के अनुसार न्यायालय को पहले यह संतुष्ट होना चाहिए कि पक्षों के बीच किया गया समझौता या समझौता वैध है।

उसी को स्वीकार करें। अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह समझौते की शर्तों की जांच करते समय अपने न्यायिक दिमाग को लागू करे पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार मुकदमे का निपटारा किया जाता है। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार समझौते की ऐसी याचिका स्वीकार हो जाने के बाद, यह न्यायालय का आदेश बन जाता है।

और न्यायिक आदेश की पवित्रता प्राप्त करता है।

12. प्रत्यर्थी की ओर से यह रुख अपनाया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश 20 सितंबर, 1991 के अपने आदेश द्वारा 27 फरवरी, 1991 के आदेश को वापस नहीं ले सकते थे और मुकदमे को उसके मूल नंबर पर बहाल कर सकते थे। यह विवादित नहीं हो सकता है कि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण के अलावा किसी अन्य कारण से 20 सितंबर, 1991 के आदेश को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन कर सकता है।

13. जब संशोधन अधिनियम ने आदेश 23 के नियम 3 के स्पष्टीकरण के साथ एक परंतुक पेश किया, जिसमें कहा गया था कि यह कहाँ है, शांत कुमार साहू और ओआरएस।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया और दूसरे द्वारा इनकार किया गया कि

समायोजन या संतुष्टि पर पहुँच गया है ", न्यायालय ने कहा।

प्रश्न का निर्णय करेगा ", वह न्यायालय जिसके समक्ष एक याचिका है

या किसी वैध के आधार पर संतुष्टि प्राप्त की गई थी समझौता की वैधता के संबंध में जांच करना

समझौता या समझौता अधिक व्यापक, परंतुक के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि एक समझौता या

समझौता "जो भारतीय संविधान के तहत अमान्य या अमान्य है।

अनुबंध अधिनियम ". के अंतर्गत विधिसम्मत नहीं समझा जाएगा।

उक्त नियम का अर्थ के साथ पढ़े गए परंतुक को देखते हुए

स्पष्टीकरण, एक न्यायालय जिसने याचिका पर विचार किया था

समझौते को यह जांचना होगा कि क्या समझौता अमान्य था

या भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अमान्य। यहाँ तक कि नियम 1 (एम) आदेश 43 को हटा दिया गया है जिसके तहत एक अपील की गई थी

समझौते को चुनौती देने वाला ऐसा पक्ष याचिका दायर कर सकता है। आदेश 23 के नियम 3 के प्रावधान के तहत, या इसके तहत अपील

संहिता की धारा 96 (1), जिसमें वह अब सवाल कर सकता है

43 के आदेश के नियम 1-ए को देखते हुए समझौते की वैधता

कोड "।

(जोर दिया गया)

90. हम इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं।

ई मामला विपन अग्रवाल और एक अन्य बनाम। रमन गंडोत्रा और आर. एस. 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1357 में अधिक विशेष रूप से पैरा 4 में रिपोर्ट किया गया

उसमें जवाब दें:

" 4. इस न्यायालय ने 'बनवारी लाल बनाम' में एक निर्णय में बताया।

चंदो देवी (श्रीमती) (एल. आर. एस. के माध्यम से) (1993) 1 एस. सी. सी. 581 आयोजित

समझौता डिक्री को पहले आवेदन दायर करने का अधिकार है
अपील को मंजूरी दी

वह न्यायालय जिसने डिक्री या

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 43 नियम 1 ए (के लिए)

संक्षेप में, सी. पी. सी. '। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 13. जब संशोधन अधिनियम ने एक परंतुक पेश किया

आदेश 23 के नियम 3 के स्पष्टीकरण के साथ कहा गया है कि कहाँ

यह एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार किया जाता है कि

समायोजन या संतुष्टि पर पहुँच गया है ", न्यायालय ने कहा।

प्रश्न का निर्णय करेगा ", न्यायालय जिसके समक्ष एक [2023] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौते की याचिका दायर की जाती है और जिसने ऐसा दर्ज किया है

समझौता, सवाल तय करना है कि क्या एक

समझौते की वैधता या समझौता अधिक परंतुक का स्पष्टीकरण कहता है कि व्यापक रूप से,

एक समझौता या समझौता जो अमान्य या अमान्य है

भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत ". माना नहीं जाएगा

उक्त नियम के अर्थ के भीतर विधिसम्मत होना। इसे ध्यान में रखते हुए

स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा गया परंतुक, एक न्यायालय जिसने

समझौता याचिका की जांच करनी होगी

भारतीय अनुबंध अधिनियम। यहां तक कि आदेश 43 का नियम 1 (एम) भी लागू किया गया है। हटा दिया गया जिसके तहत एक अपील बनाए रखने योग्य थी

आदेश 43 के नियम 1-ए को ध्यान में रखते हुए समझौता कोड "।

5. इस प्रकार अपीलार्थियों को उपचार का लाभ उठाने का अधिकार था आदेश 43 नियम 1 ए सी. पी. सी. के संदर्भ में या एक के माध्यम से अपील

डिक्री देने वाले न्यायालय के समक्ष आवेदन। इसलिए,

न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन जो

दिए गए डिक्री को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं कहा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

91. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम मानते हैं कि

-मूल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर अपील, जो समझौते की वैधता पर सवाल उठाती है, कानून में बनाए रखने योग्य थी।

92. अब हम परिस्थितियों पर गौर करेंगे, जैसा कि इस पर प्रकाश डाला गया है

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उपस्थित होने वाले वरिष्ठ वकील, प्रतिपादन

दिनांकित निपटान समझौता 28.03.1991 अमान्य है और इसके तहत बाध्यकारी नहीं है

सी. पी. सी. का आर XXIII नियम 3:

" पहला, कथित समझौता समझौते ने स्वीकार किया है कि नहीं

वादी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें स्वीकार किया गया था कि उसका हिस्सा है

एक सह-भागीदार के रूप में संपत्ति। सभी पक्षों की लिखित सहमति

आवश्यक है।

आसंता कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

दूसरा, प्रतिवादी सं. द्वारा प्रतिवादी 2 को विशिष्ट (प्लॉट सं. 140) में एक सह-आंशिक अविभाजित संपत्ति आवंटित की गई है।

1 जिस पर वादी का भी हित है।

तीसरा, समझौते और समझौते को प्रस्तुत करने वाली समझौता याचिका के बीच अंतर है। उल्लिखित भिन्नता इस प्रकार है -

(क) समझौता याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पहले से ही उसकी अपनी आय (अनुसूची बी संपत्ति) द्वारा खरीदी गई एक अन्य संपत्ति पर विचार किया जाता है जो इसका हिस्सा नहीं थी।

समझौता समझौता।

किसी भी आम सहमति का संकेत नहीं देता है, इसलिए, समझौता समझौते का निष्पादन हो जाता है अप्रभावी।

(ग) सूट संपत्ति की प्रजातियाँ, जो प्रतिवादी नं. 2 समझौते के खंड 3 (पृष्ठ 141) में था

अंतिम डिक्री कार्यवाही में उसे आवंटित किया जाएगा।

(ई) समझौते में अपने लाभ के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि समझौते में एक निश्चित खंड जोड़ा गया था। समझौता याचिका।

(च) प्रतिवादी संख्या 2 की संपत्ति के लिए सुगमता अधिकारों को समझौते में मान्यता दी गई थी और बाद में याचिका में बदल दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 को अन्य लोगों के साथ दायर करना होगा और सुगमता अधिकारों के लिए कदम उठाना होगा जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 नहीं करेगा।

वस्तु। (ज) समझौते में प्रावधान किया गया है कि प्रतिवादी नं. 2 करेंगे।

समझौता याचिका पर हस्ताक्षर करें जिसे बाद में समझौता याचिका में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने और शपथ लेने के लिए बदल दिया गया था।

चौथा, समझौते को स्वीकार करने वाले पहले अपीलीय न्यायालय के दिनांकित 01.08.2000 के फैसले में [2023] 5 एस. सी. आर. का आवंटन नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी सं. 2 को विशिष्ट रूप से आबंटित संपत्ति। प्रथम अपीलीय न्यायालय गलत आधार पर आगे बढ़ा है कि

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने अधिकारों को सौंप दिया है

प्रतिवादी नं. 1. पहली अपीलीय अदालत ने विशेष रूप से यह नोट करने में गलत किया कि समझौता समझौता वादी के अधिकारों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करता है और इसलिए इसे प्रभावी बनाया जा सकता है।

पाँचवाँ, समझौता समझौता किया गया था प्रतिवादी संख्या 2 के लिए एक छोटे से हिस्से का संकेत देते हुए, जबकि विनीता शर्मा (ऊपर) की दृष्टि से उनका बड़ा हिस्सा है। इसलिए कथित समझौते/समझौते के लिए विचार अपर्याप्त था और पूरे समझौते को

परिवर्तित और पर्यवेक्षित परिस्थितियों के कारण जमीन

कानून में परिवर्तन से प्रभावित।

अंत में, अन्यथा भी, एक सह-मालिक को एक प्रजाति में सह-स्वामित्व संपत्ति के आवंटन को प्रारंभिक डिब्री में संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, हिंदू कानून के तहत, एक सह-भागीदार द्वारा अपने अविभाजित सह-भागीदार हित का दूसरे सह-भागीदार को उपहार/त्याग/त्याग या अलगाव।

अन्य सह-भागीदारों की सहमति के बिना अमान्य है।

93. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 3 के तहत, जैसा कि अब है, जब मुकदमे में किसी दावे को किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, तो समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उनके बीच एक पूर्ण समझौता होना चाहिए। एक समायोजन का गठन करने के लिए, समझौता या समझौता स्वयं एक डिब्री में सन्निहित होने में सक्षम होना चाहिए। (देखिए: गुरप्रीत सिंह बनाम। चतुर भुज गोयल (1988) 1 एस. सी. सी. 270.)

94. निर्विवाद रूप से, हाथ में मामले में, वादी ने निपटान के विलेख पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है, जो इससे पहले प्रस्तुत किया गया था

पहली अपील में उच्च न्यायालय। वादी ने खुद को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह कभी भी अपने भाई यानी प्रतिवादी नंबर 1 और उसकी बहन यानी प्रतिवादी नंबर 2 के बीच समझौते में शामिल नहीं हुई। केवल इसी आधार पर, सभी पक्षों की किसी भी लिखित सहमति के बिना समझौता को गैरकानूनी कहा जा सकता है। संयुक्त संपत्ति के विभाजन के मुकदमे में, केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति से एक डिब्री नहीं रखी जा सकती है।

95. नित्यमोनी दासी बनाम। गोकुल चंद्र सेन ने (1911) 9 इंड केस 210 (कैल) में रिपोर्ट की, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा:

आसंता कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और पूरे मामले की फिर से सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह विभाजन के लिए एक मुकदमा है।

संयुक्त संपत्ति का, केवल कुछ लोगों के बीच सहमति से एक डिक्री

संभवतः दिलों को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

96. वीर सिंह और अन्य बनाम। खरक सिंह और अन्य

ए. आई. आर. 1925 लाह 280 में, सभी मालिकों ने सहमति नहीं दी थी

रोमिसे, मोती सागर, जे. ने कहा:

" कथित समझौते को सभी मालिकों द्वारा सहमति नहीं देना स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत था और इसलिए, न्यायालय ने इसे लागू करने से इनकार करना पूरी तरह से उचित था।

97. ताराप्रसन्ना सरकार और एक अन्य वी। कलिकामोहन

ए. आर. और अन्य ने ए. आई. आर. 1924 कैल 80 मुखर्जी और रैंकिन में रिपोर्ट किया,

एल्ड:

" जब तक सभी पक्ष समझौते में शामिल नहीं हो जाते, तब तक विभाजन मुकदमे के सभी पक्षों के लिए कोई समझौता बाध्यकारी नहीं हो सकता है:

98. उपरोक्त संदर्भ में, अब हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा किए गए निष्कर्षों पर भी गौर करेंगे, जबकि

-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर अपील। हम प्रासंगिक उद्धरण देते हैं

वैशन निम्नानुसार हैं:

" अपील प्रतिवादी नं. द्वारा दायर की गई थी। 1 इस न्यायालय के समक्ष। एफ. ए. सं. 359/96 में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की शुद्धता को चुनौती देने वाली इस अपील में समझौता याचिका दिनांक 28.3.1991, जिसे उसके द्वारा फ़्लाइड और स्वीकार किया जाता है, प्रतिवादी सं. 2 और उसी पर उसके वकील द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और वादी और उसके वकील द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि यह कानूनी समझौता नहीं है जैसा कि आदेश 23, नियम 3, सी. पी. सी. और

प्रतिवादी की ओर से सं. 2 उसका वकील नहीं कर सकता था

समझौता याचिका पर हस्ताक्षर किए क्योंकि उसने विशेष 'वकालतनामा' को निष्पादित नहीं किया है जिससे उसके वकील को प्रतिवादी नं. 1 और 2 पहली अपील में। इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायाधीश को समझौता याचिका प्राप्त नहीं करनी चाहिए थी और उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

विद्वान द्वारा समझौता याचिका की स्वीकृति

एकल न्यायाधीश को पक्षों के बीच प्रवेश करना चाहिए था

वादी सहित। उक्त कानूनी विवाद के समर्थन में, [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी नं. की ओर से विद्वान वकील द्वारा निर्भरता रखी जाती है। 2 रामास्त्रे और पुस्पा देवी (ऊपर) मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसलों पर। समझौता याचिका मुकदमे की अनुसूची संपत्तियों से भिन्न है और इसलिए, यह अमान्य है। उस समय न तो पहली अपीलीय अदालत द्वारा समझौता दर्ज किया गया था-लिखित रूप में समझौता याचिका दायर करने का, न ही पक्ष अदालत में मौजूद थे और न ही अदालत में याचिका पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, कथित समझौते को उसमें शामिल विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच समझौता नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह इस कारण से अवैध है कि यह आदेश 23, नियम 3, सी. पी. सी. का विरोध करता है। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने गुरप्रीत सिंह बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर उचित रूप से भरोसा रखा था। चतुर भुज गोयल, ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 400; और सन्यासी जेना और अन्य के मामले में इस न्यायालय का बनाम। मीना जेना और अन्य, ए. आई. आर. 1984 उड़ीसा 214। इसके अलावा विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता

प्रतिवादी नं. 1 पुस्पा देवी (उपरोक्त) के निर्णय पर प्रतिवादी सं. 2 वकील ने कहा कि समझौता याचिका अंग्रेजी में टाइप की जा रही है। इसके अलावा

उसी पर प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। 2 . प्रतिवादी नं. 1 प्रतिवादी सं. के पक्ष में सौंपे गए हिस्से के आवंटन से वंचित करने की दृष्टि से। 2 प्रतिवादी सं. द्वारा समझौता याचिका पर हस्ताक्षर करने के अभाव में वाद अनुसूची संपत्तियों के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा। 2 और कोई विशेष 'वकालतनामा' नहीं है

उसके वकील के पक्ष में निष्पादित, उक्त समझौता याचिका

यह गैरकानूनी है और इसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में स्वीकार नहीं किया जा सकता था और निचली अदालत के फैसले को संशोधित किया। इसलिए, क्रॉस

प्रतिवादी सं. द्वारा दायर आपत्ति/अपील। 2 निचली अदालत को संशोधित करके विवादित फैसले में पहली अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज समझौते को दरकिनार करके अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रतिवादी सं. के हिस्से के संबंध में निर्णय। 2 वाद अनुसूची संपत्तियों के संबंध में आवंटित। जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के विवादित निर्णय में दर्ज किया गया है, उक्त समझौते को दरकिनार करने के बाद, प्रतिवादी नं. 2 सूट अनुसूची संपत्तियों के संबंध में।

प्रशांत कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

तदनुसार दूसरे प्रतिवादी की प्रति-आपत्ति है
उपरोक्त बिंदु संख्या का उत्तर देकर अनुमति दी गई। (ग) उसमें

अनुग्रह करें।

(जोर दिया गया)

99. हम उपरोक्त निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित निर्णय और आदेश में प्रति-अपील की अनुमति देते हुए अभिलिखित किया गया।

100. तीसरा प्रश्न जो संदर्भ में हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है

न्यायालय ने न ही समझौते की शर्तों की कोई जांच की थी। यह ऐसी परिस्थितियों में है कि उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में यह पाया गया कि समझौता याचिका पर अधिवक्ता द्वारा बिना किसी स्पष्ट अधिकार के या अधिवक्ता के पक्ष में विशेष वकालतनामा के निष्पादन के बिना हस्ताक्षर किए गए थे। वास्तव में, समझौता विलेख में प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से कम कर दिया गया था।

101. उपरोक्त संदर्भ में, हम इस निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

हिमालयन कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम के मामले में न्यायालय। बलवान सिंह और अन्य ने (2015) 7 एस. सी. सी. 373, विशेष रूप से, पैरा 22 से 33 में रिपोर्ट किया, जो इस प्रकार है:

“ 22. उपरोक्त के अलावा, हमारे विचार में वकीलों को माना जाता है

अपने ग्राहक के एजेंट बनने के लिए। एजेंसी का कानून सख्ती से नहीं हो सकता है

मुवक्किल पर लागू होता है-वकीलों या एजेंटों के रूप में वकील का संबंध,

वकीलों के पास कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य होते हैं। क्योंकि

वकील भी न्यासी होते हैं, उनके कर्तव्य कभी-कभी होंगे
अन्य एजेंटों पर लगाए गए लोगों की तुलना में अधिक मांगा द.

प्राधिकरण-एजेंसी का दर्जा वकीलों को मुवक्किल के लिए कार्य करने का अधिकार देता है।

विषय पर-अनुचर की बात। सबसे बुनियादी

वकील-मुवक्किल संबंध के सिद्धांत यह हैं कि वकीलों का बकाया है।

अपने ग्राहकों के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य। उन कर्तव्यों के हिस्से के रूप में, वकील

सभी पारंपरिक कर्तव्यों को ग्रहण करें जो एजेंटों को उनके लिए देय हैं

प्रधानाचार्योँ और, इस प्रकार, ग्राहक की स्वायत्तता का सम्मान करना होगा
कम से कम [2023] 5 एस. सी. आर. के उद्देश्यों के बारे में निर्णय लें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिनिधित्व। इस प्रकार, पेशेवर जिम्मेदारी की आम तौर पर स्वीकृत धारणाओं के अनुसार, वकीलों को इसका पालन करना चाहिए। ग्राहक के निर्णय को ग्राहक के निर्णय के स्थान पर रखने के बजाय ग्राहक के निर्देश। कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक वकील को विशेष रूप से समझौता करने और समझौता करने के लिए अधिकृत होना चाहिए।

दावा करता है कि केवल अपने रोजगार के आधार पर उसके पास अपने मुवक्किल को बाध्य करने का कोई निहित या प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है।

समझौता/समझौता। इसे वैकल्पिक रूप से रखने के लिए कि एक वकील को प्रतिधारण के आधार पर, मुवक्किल के कानूनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन चुनने का अधिकार है, जबकि मुवक्किल के पास

लक्ष्य क्या होगा, यह तय करने का अधिकार। यदि विचाराधीन निर्णय उन लोगों के भीतर आता है जो स्पष्ट रूप से मुवक्किल के हैं, तो मुवक्किल से परामर्श करने में विफल रहने में वकील का आचरण या मुवक्किल के लिए निर्णय लेना, सलाहकार की अप्रभावी सहायता होने की अधिक संभावना है।

23. भारतीय बार काउंसिल नियम, 1975 (संक्षेप में "बी. सी. आई. नियम"), भाग VI अध्याय II में सभी को "व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों" का पालन करने का प्रावधान है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "1961 अधिनियम") के तहत अधिवक्ता अध्याय II की प्रस्तावना में, बी. सी. आई. नियम निम्नानुसार प्रदान करते हैं:

" एक अधिवक्ता, हर समय, एक में खुद को मान लेगा

जिस तरह से न्यायालय के एक अधिकारी, समुदाय के एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य और एक सज्जन के रूप में उनकी स्थिति के अनुरूप, यह ध्यान में रखते हुए कि जो व्यक्ति बार का सदस्य नहीं है, या बार के सदस्य के लिए उसकी गैर-पेशेवर क्षमता में क्या वैध और नैतिक हो सकता है, वह अभी भी हो सकता है

एक वकील के लिए अनुचित। पूर्वगामी दायित्व की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, एक अधिवक्ता निडरता से अपने मुवक्किल के हितों को बनाए रखेगा और अपने

आचरण अक्षर और आत्मा दोनों में उल्लिखित नियमों के अनुरूप है। इसके बाद जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, उनमें सामान्य मार्गदर्शक के रूप में अपनाए गए आचरण के सिद्धांत और शिष्टाचार शामिल हैं; फिर भी उनके विशिष्ट उल्लेख को दूसरों के अस्तित्व के समान रूप से इनकार के रूप में नहीं माना जाएगा।

अनिवार्य हालांकि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

24. प्रस्तावना में यह अनिवार्य किया गया है कि एक अधिवक्ता को अत्यंत जिम्मेदार शांत कुमार साहू और ओआरएस में अपना और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

तरीके से। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति बार का सदस्य नहीं है, या जो बार का सदस्य अपनी गैर-पेशेवर क्षमता में है, उसके लिए क्या उचित और वैध हो सकता है।

25. उक्त अध्याय 2 की धारा 2 में निम्नलिखित कर्तव्यों का प्रावधान है - अपने मुवक्किल की ओर वकालत करें। बी. सी. आई. नियमों के नियम 15 और 19, विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक हैं और इसलिए, वे हैं -

नीचे निकाला गया है:

“ 15. एक अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह निडरता से अपने या किसी अन्य के लिए किसी भी अप्रिय परिणाम की परवाह किए बिना अपने मुवक्किल के हितों को सभी निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीकों से बनाए रखे। वह अभियुक्त के अपराध के बारे में उसकी व्यक्तिगत राय की परवाह किए बिना अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का बचाव करेगा, यह ध्यान में रखते हुए कि उसकी वफादारी कानून के प्रति है जिसके लिए आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त सबूत के बिना दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

19. एक वकील अपने मुवक्किल या उसके अधिकृत एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पर कार्य नहीं करेगा।

उसके मुवक्किल या उसके अधिकृत अभिकर्ता के निर्देश। इसके अलावा, उक्त धारा II के अध्याय I में बी. सी. आई. नियम प्रदान करते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता अपने अभ्यास के मामले में

1961 के अधिनियम की धारा 30 में उल्लिखित कानून का पेशा कुछ प्रतिबंधों के अधीन होगा। इनमें से एक

खंड (सी. सी.) में निहित प्रतिबंध निम्नानुसार हैं:

" (ग) तथापि, एक वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्ठ के निर्देश पर अपने मुवक्किलों की ओर से बहस के दौरान रियायतें देने या वचन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

अधिवक्ता "।

27. इसके अलावा, बार द्वारा निर्धारित "आचार संहिता"

भारतीय परिषद, विकास की मान्यता में

कानूनी समुदाय के भीतर पेशेवर और नैतिक मानक, [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ नियमों के लिए प्रावधान करता है जिसमें आचरण और शिष्टाचार के नियम होते हैं जो सामान्य मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए

अभ्यास और पेशा। उक्त संहिता के अध्याय III में "मुवक्किल के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य" का प्रावधान है। नियम 26 के तहत आदेश दिया गया है कि एक वकील कोई समझौता नहीं करेगा।

या उचित और विशिष्ट निर्देशों के बिना रियायत

उसका ग्राहक"। यह ध्यान देने योग्य है कि संहिता के तहत एक अधिवक्ता में स्पष्ट रूप से अधिवक्ताओं का एक समूह और एक कानून शामिल है

फर्म जिसका भागीदार या सहयोगी ग्राहक के लिए कार्य करता है।

28. इसलिए, बी. सी. आई. नियम यह आवश्यक बनाते हैं कि इसके बावजूद

अभ्यास की विशिष्ट कानूनी धारा, बार में वरिष्ठता या

एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में एक अधिवक्ता का पदनाम, नैतिक

न्यायालय के समक्ष रियायतें समान रहती हैं। वकीलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कोई भी रियायत देने से पहले मुवक्किल या अधिकृत एजेंट से आवश्यक निर्देश प्राप्त करें। मुवक्किल के लिए और उसकी ओर से अदालत के समक्ष बयान।

29. जबकि बी. सी. आई. नियम और अधिनियम, कोई अपवाद नहीं हैं।

इससे पहले निर्देश प्राप्त करने वाले अधिवक्ता की आवश्यकता के लिए

न्यायालय के समक्ष मुवक्किल की ओर से कोई रियायत देते हुए, यह न्यायालय पेरियार और पारीकत्री रबर लिमिटेड बनाम। की स्थिति

केरल [(1991) 4 एस. सी. सी. 195] ने सुई जेनरिस की स्थिति और अधिवक्ता द्वारा प्राप्त जिम्मेदारी की स्थिति को देखा है।

उनके द्वारा दिए गए बयानों के संबंध में जनरल

अदालतें। उक्त अवलोकन इस प्रकार है: (एस. सी. सी. पी. 209 , पैरा

19)

“ 19 .

सरकारी प्लीडर द्वारा दी गई कोई भी रियायत

विचारण न्यायालय में सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह

जाहिर है, हमेशा, राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील द्वारा दी गई गलत या गलत या अनावश्यक रियायत पर भरोसा करना असुरक्षित है, जब तक कि वह जिम्मेदार अधिकारी के निर्देशों पर लिखित रूप में न हो। अन्यथा यह सरकारी खजाने पर अनावश्यक और अनावश्यक रूप से भारी बोझ डाल देगा। लेकिन द.

एक ही पैमाना तब लागू नहीं किया जा सकता जब अधिवक्ता

जनरल ने तब से बार में एक बयान दिया है

महाधिवक्ता सभी के साथ बयान देते हैं

जिम्मेदारी "। आसंता कुमार साहो और ओआरएस। वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(देखिए: जोगिंदर सिंह वासू बनाम। पंजाब राज्य [(1994) 1

एस. सी. सी. 184])

30. प्रिवी काउंसिल, सौरेन्द्र नाथ मित्रा बनाम। तरुबाला दासी [(1929-30) 57 IA 133: (1930) 31 एलडब्ल्यू 803: ए. आई. आर. 1930 पी. सी. 158] ने निम्नलिखित दो टिप्पणियों की हैं जो वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं: (आई. ए पी. 140-41) " दो अवलोकन जोड़े जा सकते हैं। सबसे पहले, वकील का निहित अधिकार पद का एक उपांग नहीं है, एक गरिमा जो अदालतों द्वारा बैरिस्टर या कानून में अधिवक्ता के दर्जे में जोड़ी गई है। यह मुवक्किल के हित में निहित है, ताकि अधिवक्ता के रूप में उसकी नियुक्ति को पूरा लाभकारी प्रभाव दिया जा सके। दूसरा, निहित प्राधिकरण को हमेशा ग्राहक के स्पष्ट निर्देशों द्वारा रद्द किया जा सकता है। कोई वकील वास्तविक नहीं है

ग्राहक के सही कानूनी अधिकार को प्रत्यक्ष या दूरस्थ रूप से प्रभावित करने वाली कोई भी रियायत देने से पहले ग्राहक या उसके अधिकृत एजेंट से उचित निर्देश लेना हमेशा बेहतर होता है। अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करता है और मुवक्किल की ओर से कार्यवाही करता है। वह अदालत और मुवक्किल के बीच एकमात्र कड़ी है। इसलिये उनका जिम्मेदारी भारी है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने फैसले को बदलने के बजाय अपने मुवक्किल के निर्देशों का पालन करेंगे।

32. आम तौर पर, एक वकील द्वारा किए गए तथ्य की स्वीकृति उनके प्रधानाचार्यों पर तब तक बाध्यकारी होती है जब तक वे स्पष्ट होते हैं; हालाँकि, जहाँ एक कथित स्वीकारोक्ति के बारे में संदेह मौजूद है, अदालत को इस तरह के प्रवेश को तब तक स्वीकार करने के लिए सावधान रहना चाहिए जब तक कि वकील या अधिवक्ता उसके द्वारा अधिकृत नहीं हो जाता है।

इस तरह के प्रवेश करने के लिए प्रिंसिपल। इसके अलावा, एक मुवक्किल किसी ऐसे बयान या स्वीकारोक्ति से बाध्य नहीं है जिसे देने के लिए वह या उसका वकील अधिकृत नहीं था। एक वकील के पास आम तौर पर कोई निहित [2023] 5 एस. सी. आर. नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या एक स्वीकार या बयान देने के लिए स्पष्ट प्राधिकरण

जो सीधे आत्मसमर्पण करेगा या सारगर्भित निष्कर्ष निकालेगा

ग्राहक के कानूनी अधिकार जब तक कि ऐसी स्वीकृति या बयान न हो

स्पष्ट रूप से उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उचित कदम है जिसे वकील नियुक्त किया गया था।
हम न तो जोड़ने के लिए जल्दी करते हैं

मुवक्किल और न ही अदालत वकील के बयानों से बाध्य है या

कानून या कानूनी निष्कर्षों के मामलों में प्रवेश। इस प्रकार, पेशेवरों की आम तौर पर स्वीकृत
धारणाओं के अनुसार

जिम्मेदारी, वकीलों को मुवक्किल के निर्देशों का पालन करना चाहिए

उनके निर्णय को मुवक्किल के निर्णय के स्थान पर रखने के बजाय। हम.

यह जोड़ा जा सकता है कि कुछ मामलों में वकील निर्णय ले सकते हैं

ग्राहक के लिए आरक्षित। यह अक्सर कहा जाता है कि वकील कर सकता है ग्राहक से परामर्श किए
बिना रणनीति के बारे में निर्णय लें, जबकि

ग्राहक को ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है जो उसे प्रभावित कर सकते हैं।

33. हम इस चर्चा को लंबा करने का इरादा नहीं रखते हैं। हम कर सकते हैं लॉर्ड ब्रोहम के एक
प्रसिद्ध कथन को ध्यान में रखते हुए समापन करें:

" एक अधिवक्ता, अपने कर्तव्य के निर्वहन में जानता है लेकिन एक

दुनिया में व्यक्ति और वह व्यक्ति उसका ग्राहक है। [एडा :

यह बयान श्री हेनरी ब्रोहम ने उनके रूप में दिया था।

लॉर्डशिप तब रानी कैरोलिन का बचाव करते हुए था

इंग्लैंड, बार्टोलोमियो के साथ "व्यभिचार" के लिए
बर्गामी, वॉल्यूम II, पी। 2 जिसमें महामहिम का बचाव है,

जॉन फेयरबर्न, ब्रॉडवे द्वारा मुद्रित और प्रकाशित,

लुडगेट हिल (1820)।] "

(जोर दिया गया)

102. हम इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख करते हैं

एम पेस्टनजी गरीवाला (ऊपर), विशेष रूप से, अवलोकन

पैरा 37 में, जो इस प्रकार है:

“ 37. हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह विवेकपूर्ण होगा।

वकील के लिए निहित अधिकार पर कार्य नहीं करने के लिए सिवाय इसके कि कब

समझौते या समझौते द्वारा मुकदमे का तत्काल समायोजन और अनुचित आशा कुमार साहू और ओ. आर. एस. के बिना पक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।

वी. चारुलता साहू और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विलम्ब। आसान और तेज़ संचार के इन दिनों में, ऐसी आकस्मिकता शायद ही कभी उत्पन्न हो।
एक बुद्धिमान और सावधान

इन सभी को पूरा करने के लिए लिखित रूप में व्यक्त आवश्यक प्राधिकरण आकस्मिकताएँ ताकि न
तो उसका अधिकार और न ही अखंडता

कभी संदेह होता है। यह आवश्यक सावधानी सुरक्षा करेगी

वकील की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के साथ-साथ प्रतिष्ठा को बनाए रखें

और कानूनी पेशे की गरिमा।

(जोर दिया गया)

103. लगभग छह दशक पहले, मद्रास उच्च न्यायालय बोल रहा था
के मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी (जैसा कि उनका प्रभुत्व तब था)
नंदम्मल वी। मारिमुथु मिस्त्री और अन्य ने आकाशवाणी में रिपोर्ट किया
मैड 7 ने सावधानी का संकेत देते हुए कहा था:

" 5. निर्णय काफी स्पष्ट प्रतीत होते हैं कि यहां तक कि

अपने ग्राहक से। लेकिन ग्राहकों की दुनिया की वर्तमान स्थिति में और वह स्थिति जिसमें बार अब
खुद को पाता है और

विभाजित न्यायिक प्राधिकरण का चेहरा और वैधानिकता का अभाव

विवेक का समर्थन करना यह निर्धारित करता है कि जब तक व्यक्त करने की शक्ति नहीं दी जाती है
वकालतनामा में ही समझौता करने के लिए,

एक विशेष प्राप्त करने के सामान्य अभ्यास के अनुसार

वकालतनामा दाखिल किया जाना चाहिए या विशिष्ट सहमति

समझौता करने वाले पक्ष को प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि एक

शिकायत आदि पर समर्थन किया जाता है, बेहतर होगा कि

पार्टी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएँ

इसलिए, यह स्पष्ट करते हुए कि पार्टी को पता है कि क्या है

वकील द्वारा उसकी ओर से किया जा रहा है।

104. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम मानते हैं कि

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की कि दोनों के बीच समझौता बचावकर्ता संख्या 1 और 2 जवाब गैरकानूनी था।

हमारे अंतिम निर्णय

105. हम अपने अंतिम निष्कर्ष निम्नानुसार निकाल सकते हैं:

(i) निचली अदालत द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक डिक्री, जिसकी पुष्टि की गई है।

उच्च न्यायालय द्वारा इस हद तक संशोधित किया गया है कि बेटियाँ [2023] 5 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वे शिकायत में निर्धारित सभी संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से के हकदार हैं, अर्थात् स्वर्गीय श्री कुमार साहू की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्तियों में। विचारण न्यायालय तदनुसार डिक्री में संशोधन करेगा।

जैसा कि हमने माना है कि मूल प्रतिवादी संख्या के बीच समझौता। 1 और 2 जवाब कानून के अनुसार नहीं था, यहाँ अपीलार्थी मूल प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से के हकदार नहीं होंगे।

अपीलार्थी केवल अपने एक तिहाई हिस्से के हकदार होंगे।

सूट गुण।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए अपीलार्थी अब विचारण न्यायालय के समक्ष लेखा प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त स्पष्टीकरणों के साथ, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और

बर्खास्त कर दिया।

यह मुकदमा अब तक लगभग चार दशक पुराना है। आज की तारीख में मूल लगभग 85 वर्ष पुराना है। ऐसी परिस्थितियों में, इस निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति के तीन महीने की अवधि के भीतर अंतिम डिक्री तैयार की जाएगी।

दल अपना खर्च स्वयं वहन करें। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

याचिकाएं खारिज कर दी

गई।

शेवाली मोंगा, एलसीआरए)